हिन्दी साप्ताहिक

भारत निविदा लाईन समाचार

भारत निविदा लाईन समाचार पत्र क्राइम की हर खबर....

■ वर्ष : 19 ■ अंक: 24 ■ नई दिल्ली 10 से 16 अप्रैल 2026 ■ पृष्ठ : 08 ■ मूल्य : 02 रुपए

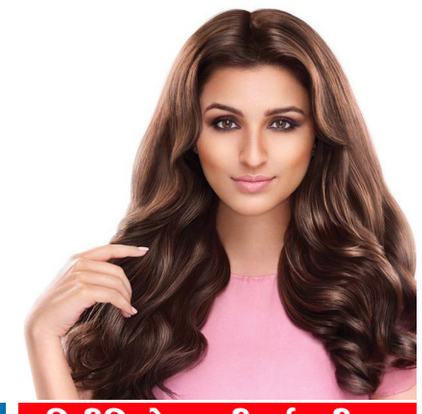

परिणीति चोपड़ा की नई पारी शुरू

एक नजर

राष्ट्रपति भवन में 18 अप्रैल को 'चेंज ऑफ गार्ड' समारोह नहीं होगा

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होने वाला साप्ताहिक 'चेंज ऑफ गार्ड' समारोह इस शनिवार (18 अप्रैल) को आयोजित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के अनुसार यह निर्णय कोरिया के राष्ट्रपति के आगामी राजकीय दौरे के मद्देनजर होने वाली औपचारिक स्वागत समारोह के पूर्वाभ्यास के कारण लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग 19 से 21 अप्रैल तक भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। यह उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। उनके साथ प्रथम महिला किम हे क्युंग तथा मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।

मार्च में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने 1.81 लाख से अधिक शिकायतों का निवारण किया

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने बताया है कि मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा कुल 1,81,279 शिकायतों का निवारण किया गया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के काम पर केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की गुरुवार को जारी 47वीं मासिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। विभाग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि लगातार 45वें महीने केंद्रीय सचिवालय में मासिक शिकायत निस्तारण का स्तर एक लाख मामलों से ऊपर रहा। विज्ञप्ति के अनुसार मार्च 2026 के लिए जारी शिकायत निवारण सहायता एवं सूचकांक (जीआएआई) रैंकिंग में ग्रुप ए श्रेणी में वित्तीय सेवा विभाग (बीमा प्रभाग), दूरसंचार विभाग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क तथा ग्रुप बी श्रेणी में राजभाषा विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय शीर्ष पर रहे।

महिला आरक्षण में रोड़ा अटकाना चाहता है विपक्ष : भाजपा

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण में रोड़ा अटकाने के लिए बहाने तलाश रहा है और इसे परिसीमन से जोड़कर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। भाजपा के तेजस्वी सूर्या ने संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026, और उससे जुड़े दो अन्य विधेयकों पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा कि यह विधेयक ऐतिहासिक है। इससे पहले करीब छह बार यह विधेयक सदन में आया और इसे जानबूझकर पारित नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने तो इस विधेयक को फाड़कर विधेयक को अटकाने का काम किया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वजह से ही नारी वंदन अधिनियम को सदन में पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष परिसीमन के बहाने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध कर रही है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष परिसीमन के बहाने महिला आरक्षण विधेयक को रोकना चाहती है। विपक्ष दक्षिण भारत के लोगों को इस विधेयक के माध्यम से गुमराह कर रही है। इस परिसीमन के माध्यम से छोटे राज्यों को फायदा होगा।

उन्होंने विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि परिसीमन का क्रियाकलाप पिछले दरवाजे से नहीं बल्कि संविधान के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शासन व्यवस्था अच्छी और लोगों की पहुंच निर्वाचित प्रतिनिधि तक आसान बनाने के लिए परिसीमन किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप बेबुनियाद है। मोदी सरकार संवैधानिक दायित्वों को निर्वाहन कर रही है। मोदी सरकार टालने की नीति में विश्वास नहीं करती है बल्कि समस्याओं का समाधान करती है।

सैन्य टकराव से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर डॉ. क्रिश्चियन स्टॉकर के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि सैन्य टकराव से समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम एक स्थिर, टिकाऊ और स्थायी शांति का समर्थन करते हैं।

पीएम मोदी में कहा, चांसलर स्टॉकर, आपकी पहली भारत यात्रा पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें बहुत खुशी है कि आपने यूरोप के बाहर अपनी पहली यात्रा के लिए भारत को चुना। ये आपके विजन और भारत-ऑस्ट्रिया संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चार दशकों के बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर की भारत यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 के ऐतिहासिक भारत-यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों में एक नए सुनहरे अध्याय की शुरूआत हुई है। चांसलर स्टॉकर की इस यात्रा से भारत-ऑस्ट्रिया संबंधों को भी एक नए कालखंड में ले जाया जा रहा है।

पीएम मोदी ने कहा कि अवसंरचना, नवाचार और स्थिरता में भारत और ऑस्ट्रिया भरोसेमंद साझेदार रहे हैं। दिल्ली मेट्रो हो या हिमालय पर 10 हजार फीट की ऊंचाई पर बना अटल टनल, ऑस्ट्रिया की सुरंग निर्माण विशेषज्ञता ने अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। इतना ही नहीं, रेलवे प्रोजेक्ट्स से लेकर गुजरात के गिरनार रोपवे तक, क्लीन एनर्जी से लेकर अर्बन डेवलपमेंट तक, भारत के कई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में ऑस्ट्रियन कंपनियां सक्रिय भागीदार रही हैं।

उन्होंने कहा कि चांसलर स्टॉकर की यह यात्रा ट्रेड और इनवेस्टमेंट में नई ऊर्जा लाएगी। मुझे खुशी है कि वे बड़े विजन और एक बड़े बिजनेस डेलिगेशन के साथ भारत आए हैं। भारत की स्पीड और स्केल को जोड़कर पूरी दुनिया के लिए विश्वसनीय तकनीक और सप्लाई चेन सुनिश्चित करेंगे। हम डिफेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भी अपनी साझेदारी को सुदृढ़ करेंगे। साथ ही, हम इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन सहयोग को भी और मजबूत करेंगे। आईआईटी दिल्ली और ऑस्ट्रिया की मोंटान यूनिवर्सिटी के बीच आज साइन किया जा रहा एमओयू इस नॉलेज एक्सचेंज का एक उज्ज्वल उदाहरण है।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत का टैलेंट, ऑस्ट्रिया की इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की क्षमता रखता है। 2023 में हमने ऑस्ट्रिया के साथ एक व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किया था। अब इस एग्रीमेंट के अंतर्गत, हम नर्सिंग सेक्टर में भी मोबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे। हम जॉइन्ट रिसर्च और स्टार्टअप सहयोग को भी और मजबूत करेंगे। यूथ एक्सचेंज को प्रमोट करने के लिए, हम आज भारत-ऑस्ट्रिया वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे हैं।

बता दें कि एक ऐसा समझौता है जिसके तहत भारत और ऑस्ट्रिया के युवा एक-दूसरे के देश में कुछ समय के लिए रहकर काम और यात्रा दोनों कर सकते हैं।

दुनिया के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करेंगे भारत और ऑस्ट्रिया : मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के क्षेत्र में नयी ऊर्जा आयेगी और ऑस्ट्रिया की विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता तथा भारत की गति और पैमाना दुनिया के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करेगा। दोनों देश रक्षा, सेमीकन्डक्टर, क्वांटम और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अपनी साझेदारी को सुदृढ करेंगे। भारत और आस्ट्रिया ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं और माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट को नर्सिंग क्षेत्र में भी आगे बढाने का निर्णय लिया है। दोनों देशों ने युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत हॉलिडे प्रोग्राम शुरू करने की भी घोषणा की है। श्री मोदी ने भारत यात्रा पर आये श्री स्टॉकर के साथ वार्ता के बाद गुरुवार को यहां संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि भारत-आस्ट्रिया साझेदारी को नवाचार और भविष्य की जरुरतों पर आधारित बनाये जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का मजबूती से मानना है कि सैन्य टकरावों से समस्याओं का समाधान संभव नहीं और हम यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि भारत और आस्ट्रिया दोनों ही वैश्विक संस्थाओं में सुधारों के प्रबल समर्थक हैं और आतंकवाद को जड़ से मिटाना, हमारी साझी प्रतिबद्धता है।

पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा विश्व एक बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है और इसका प्रभाव हम सभी पर पड़ रहा है। ऐसे तनावपूर्ण वैश्विक माहौल में, भारत और ऑस्ट्रिया हम एकमत हैं कि सैन्य टकराव से समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम एक स्टेबल, सस्टेनबल और स्थायी शांति का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत हैं कि बढ़ते ग्लोबल चुनौतियों के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अनिवार्य है और आतंकवाद को जड़ से मिटाना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। 2024 में मेरी ऑस्ट्रिया की यात्रा भी चार दशकों बाद हुई थी। उस विजिट के बाद आज ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर का भारत में स्वागत करना हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है।

महिला आरक्षण बिल पर भिड़े अमित शाह और अखिलेश

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच तीखी बहस देखने को मिली। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए तो गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। इसी बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हस्तक्षेप करना पड़ा।

अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? पहले जनगणना से शुरूआत करें। साथ ही उन्होंने दोहराया कि उनकी पार्टी सैद्धांतिक रूप से महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन परिसीमन के जरिए इसे लागू करने का विरोध करती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर जनगणना में देरी कर रही है, ताकि जातिगत जनगणना और आरक्षण के विस्तार की मांगों को उठने से रोका जा सके। अखिलेश यादव ने कहा कि वे जनगणना में इसलिए देरी कर रहे हैं, क्योंकि जब यह होगी, तो हम जाति-आधारित जनगणना की मांग करेंगे और वे ऐसा नहीं चाहते।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जनगणना का काम पहले ही शुरू हो चुका है और उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि जाति आधारित जनगणना भी कराई जाएगी।

गृह मंत्री ने कहा कि अभी हाउस लिस्टिंग (घरों की गिनती) चल रही है घर किसी खास जाति के नहीं होते। अगर समाजवादी पार्टी की चली, तो वह घरों को भी कोई जाति दे देगी। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि जनगणना होगी और उसके साथ जातिगत जनगणना भी होगी।

सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी महिला आरक्षण बिल का तब तक समर्थन नहीं करेगी, जब तक इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रावधान शामिल नहीं किए जाते। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान के तहत धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए किसी भी तरह का आरक्षण असंवैधानिक है।

महिला आरक्षण का जिसने विरोध किया, महिलाओं ने उसका बुरा हाल किया : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, एजेंसी। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में संबोधन के दौरान कहा कि आज सुबह से चर्चा शुरू हुई है। जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं। उस समय समाज की मनोस्थिति और नेतृत्व की क्षमता उस पल को कैप्चर करके एक राष्ट्र की अमानत बना देती है, एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती है।

उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यह वैसा ही पल है। आवश्यकता तो ये थी कि 25-30 वर्ष पहले जब आवश्यकता महसूस हुई तो हम इसको लागू कर देते और काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते, आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर सुधार भी होते। यही लोकतंत्र की ड्यूटी होती है। हमारी हजारों वर्ष की लोकतंत्र की विकास यात्रा रही है। विकास यात्रा में नया आयाम जोड़ने का शुभ अवसर सदन के सभी साथियों को मिला है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है।

लोकसभा में पेश किया गया संविधान संशोधन विधेयक 2026

नई दिल्ली। लोकसभा में गुरुवार को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 को पेश करने की मंजूरी मिल गई। महिलाओं के आरक्षण और परिसीमन को लागू करने के उद्देश्य से लाए गए इस अहम विधेयक को सदन में मत विभाजन के बाद स्वीकृति दी गई। विपक्ष की मांग पर वोटिंग की औपचारिक प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके बाद मत विभाजन कराया गया। इस दौरान 251 सांसदों ने विधेयक के समर्थन में वोट दिया जबकि 185 सांसदों ने इसका विरोध किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने परिणाम घोषित करते हुए बताया कि आंकड़े परिवर्तन के अधीन हो सकते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में खड़े होकर इस विधेयक को पेश किया, जो विधायी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मैं चाहता हूं कि सभी सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने न दें। हम सब मिलकर देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला है।

पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत, एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व में भी आज भारत की स्वीकृति हम सब महसूस कर रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव का पल है। यह समय हमारे पास आया है। इस समय को हमने एक ह्यविकसित भारतह्ल के संकल्प के साथ जोड़ा है। मैं मानता हूं कि केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े से ही 'विकसित भारत' की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं।

महिला आरक्षण को परिसीमन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए : गौरव गोगोई

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों पर चर्चा के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बिल पर बोलते हुए कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

गौरव गोगोई ने कहा कि कानून मंत्री की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार सदन में महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही हो। उन्होंने याद दिलाया कि तीन साल पहले भी गृह मंत्री ने इसी तरह की बातें कही थीं और दोनों भाषणों में काफी समानता है।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रही है लेकिन उनकी मांग है कि इसे सरल बनाया जाए ताकि बिल पारित होते ही लागू हो सके। उन्होंने कहा कि इसे परिसीमन के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने भी संविधान (131वां संशोधन) विधेयक का विरोध किया। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से गैरकानूनी और असंवैधानिक कदम बताया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि साल 2023 में उनकी पार्टी ने 2024 के आम चुनाव से ही महिला आरक्षण लागू करने का समर्थन किया था लेकिन सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी।

उन्होंने आरोप लगाया कि अब सरकार महिला आरक्षण के मुद्दे का इस्तेमाल एक खतरनाक परिसीमन प्रक्रिया लागू करने के लिए कर रही है, जिससे पूरे देश में राजनीतिक सीमाओं को अपने हिसाब से बदला जा सके, जैसा कि जम्मू-कश्मीर और असम में किया गया।

वेणुगोपाल ने कहा कि यह बिल भारत के संघीय ढांचे पर सीधा हमला है और इसे वापस लिया जाना चाहिए।

इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केसी वेणुगोपाल बिल के गुण-दोष पर इस चरण में सवाल नहीं उठा सकते बल्कि केवल तकनीकी आपत्तियां ही दर्ज कर सकते हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान विपक्ष को 'करारा जवाब' देगी।

परमाणु ऊर्जा :भारत चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल, संसद ने जताया वैज्ञानिकों का आभार

नई दिल्ली, एजेंसी। देश की वैज्ञानिक प्रगति और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी गुरुवार को संसद में रखी गई। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन को बताया कि 6 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के कल्पक्कम में भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। देश के 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने पहली बार क्रिटिकलिटी प्राप्त कर ली है। इसका अर्थ है कि रिएक्टर में नियंत्रित और सतत परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया सफलतापूर्वक शुरू हो गई है।

सदन को अवगत कराते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि दो दशकों से अधिक समय तक वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, उद्योगों और परमाणु ऊर्जा विभाग के हजारों कर्मियों के सतत प्रयासों का परिणाम है। यह उपलब्धि भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन को मजबूती देने के साथ ही वर्ष नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। सदन में बताया गया कि इस रिएक्टर का कोर लोडिंग मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में किया गया था। भारत की परमाणु नीति तीन चरणों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य सीमित यूरेनियम संसाधनों और प्रचुर थोरियम भंडार का अधिकतम उपयोग करना है।

पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग कर प्रेसराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर के माध्यम से प्लूटोनियम तैयार किया जाता है। दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के जरिए प्लूटोनियम से अधिक परमाणु ईंधन उत्पन्न किया जाएगा। इस तकनीक की खासियत यह है कि यह जितना ईंधन खर्च करता है, उससे अधिक पैदा भी कर सकता है। तीसरे चरण में थोरियम आधारित रिएक्टर विकसित किए जाएंगे, जिससे दीर्घकालिक और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित होगा। सदन को यह भी बताया गया कि दिसंबर 2025 में पारित परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कानून के माध्यम से इस क्षेत्र को व्यापक भागीदारी के लिए खोला गया है। देश 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह रिएक्टर पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। इसका डिजाइन इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने तैयार किया है, जबकि निर्माण भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम द्वारा किया गया है, जिसमें भारतीय उद्योगों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। गौरतलब है कि देश की इस उपलब्धि के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जिन्होंने इस उन्नत तकनीक में महारत हासिल की है। इसे देश की वैज्ञानिक क्षमता, नवाचार और सामूहिक प्रयास का प्रतीक बताया गया। सदन में कहा गया कि यह उपलब्धि न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह भारत के सुरक्षित, टिकाऊ और आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव भी रखती है। पूरे सदन ने इस ऐतिहासिक सफलता के लिए सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और संबंधित सभी हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ युवा कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन, सख्त कार्रवाई की मांग

दुर्गेश कुमार गुप्ता

माध्य प्रदेशः शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती व्यावसायिक प्रवृत्तियों को लेकर ब्यौहारी में अब आवाज बुलंद होने लगी है। ब्लॉक युवा कांग्रेस कमेटी, ब्यौहारी ने निजी स्कूलों की कथित मनमानी के खिलाफ प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है।

इस संबंध में समिति के अध्यक्ष आयुष्मान ताम्रकार के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होते ही क्षेत्र के कई निजी विद्यालयों ने बिना किसी ठोस आधार के ट्यूशन फीस और अन्य शुल्कों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी न केवल शासन के नियमों के विपरीत बताई जा रही

है, बल्कि मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों के लिए गंभीर आर्थिक संकट का कारण भी बन रही है। किताबों और ड्रेस में ह्यफिक्सिंगह्ल का आरोप मामले का सबसे चिंताजनक पहलू यह सामने आया है कि कई स्कूलों द्वारा चुनिंदा निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें अनिवार्य कर दी गई हैं। अभिभावकों को इन्हें केवल स्कूल द्वारा तय की गई विशेष दुकानों से ही खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। आरोप है कि इन दुकानों और स्कूल प्रबंधन के बीच कमीशन आधारित गठजोड़ है, जिससे अभिभावकों को अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है।

यही स्थिति स्कूल ड्रेस के मामले में भी देखने को मिल रही है, जहां निर्धारित दुकानों से ही यूनिफॉर्म खरीदना अनिवार्य किया जा रहा है। बाजार में इन वस्तुओं की स्वतंत्र उपलब्धता न होने से अभिभावक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग युवा कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा है कि यह पूरा मामला ह्लशिक्षा के नाम पर खुली कालाबाजारीह्ल का उदाहरण है। संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि इस पर तत्काल जांच कर दोषी स्कूलों और संबंधित पक्षों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके।

आंदोलन की चेतावनी

ब्लॉक युवा कांग्रेस कमेटी ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो संगठन व्यापक स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।

स्थानीय अभिभावकों में रोष। इस पूरे मुद्दे को लेकर अभिभावकों में भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकता को मुनाफे का जरिया बनाना बेहद चिंताजनक है और इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। अब निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इस गंभीर मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है और आम जनता को राहत दिलाने के लिए कितनी जल्दी कदम उठाता है।

रामपुर मनिहारान में एंटी रोमियो टीम का मिशन शक्ति अभियान, महिलाओं व बालिकाओं को किया गया जागरूक

घनश्याम दास

उत्तर प्रदेशः सरकार द्वारा संचालित पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर माननीय अभिनंदन सिंह के निदेर्शानुसार नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेतृत्व एंव उपनिरीक्षक श्री प्रवेश शर्मा की देखरेख में नगर के अनेकों स्थानों पर मिशन शक्ति अभियान फेज 0,5 के दूसरे चरण के अंतर्गत सुरक्षात्मक अभियान चलाया गया।

15 अप्रैल बुधवार को एंटी रोमियो टीम इंचार्ज उपनिरीक्षक श्री प्रवेश शर्मा , महिला कांस्टेबल 1877 सोनू , 938 गुंजन व होमगार्ड 541 सविता द्वारा रामपुर मनिहारान के शहरी पुल, पीठ बाजार, मैन बाजार , इस्लामनगर रोड, संजय चौक एंव सराफा बाजार में महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेज 0,5 के तहत साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान के क्रम में बालिकाओं को डिजिटल अरेस्टिंग व नारी सशक्तिकरण एवं सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में बताया गया और उनके अधिकारों सुरक्षा और संरक्षण के विषयों से जागरूक किया गया। साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम के बारे में भी जागरूक किया गया,महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षात्मक व्यवस्था हेतू सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 1090 वूमेन पावर,1030 साइबर अपराध, 108 एंबुलेंस सेवा तथा 112 पुलिस आपातकालीन सेवा आदि के बारे में जानकारी दी गई और कहा गया कि महिला व छात्रा/बालिकाएं किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्तिथि को देखते हुए निर्भीक होकर उपरोक्त नम्बरों द्वारा सहायता प्राप्त कर सकती हैं, पुलिस टीम 24 घंटे आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है इसी जागरूकता अभियान के साथ विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने हेतू एंटी रोमियो टीम द्वारा पंपलेट भी विस्तृत किए गए।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की प्रगति को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई आयोजित

मोहम्मद फि रोज आलम

बिहारः श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार की अध्यक्षता में ब्रेडा विभाग द्वारा क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस समीक्षात्मक बैठक में Bihar Renewable Development Agency के मुख्य अभियंता, ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन का कार्य कर रही विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधि तथा केंद्रीकृत अनुश्रवण प्रणाली विकसित करने वाली amnex infotechnologies pvt ltd के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार ने स्पष्ट रूप से कहा कि अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का प्रत्यक्ष लाभ ग्रामीण परिवेश में रहने वाले आम नागरिकों को अधिकतम रूप से मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन एजेंसियों द्वारा

अब तक शत-प्रतिशत अधिष्ठापन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, वे इस माह के अंत तक हर हाल में अधिष्ठापन कार्य पूर्ण करें।

निदेशक द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि योजना की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और योजना समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण की जा सके। इस अवसर पर आयोजित समीक्षात्मक बैठक में श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कर्मी भी उपस्थित रहे।

बिहान योजना से सियामुनी बनीं आत्मनिर्भर, मजदूरी से व्यवसाय तक का सफर

प्रभेश मिश्रा

छत्तीसगढ़ः सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत महेशपुर की सियामुनी राजवाड़े आज अपने गाँव की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन चुकी है। कभी कृषि और दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर रहने वाली सिया मुनि की पहचान अब एक सफल व्यवसायी के रूप में हो चुकी है। यह बदलाव संभव हो पाया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ह्यबिहानह्ल योजना की बदौलत। स्वयं सहायता समूह में जुड़ने से पहले सियामुनी राजवाड़े दीदी का परिवार एक छोटा परिवार है जिसमें कुल 6 सदस्य है। उनकी आजीविका का मुख्य स्त्रोत कृषि कार्य, वनोपज संग्रहण एवं अन्य गैर कृषि कार्य कर रहे है। सामान्य ग्रामीण जीवन शैली एवं रोज की तरह घर के काम-काज खाना बनाना एवं कृषि कार्य में ही व्यस्त रहते थे। अपने लिए चाह कर भी

समय नहीं निकाल पाते थे। घर की जिम्मेदारियों के बीच खुद की कुछ करने की चाह को दबा कर रख लेती थी कृषि पर आधारित होने के कारण आय का कोई दूसरा स्त्रोत नहीं होने के कारण आए दिन पैसों की आवश्यकता रहती थी। स्वयं सहायता समूह में जुड़ने से पहले प्राथमिक आजीविका कृषि एवं दैनिक मजदूरी करती थी जिससे कृषि से आय 23000 वार्षिक एवं मजदूरी से आय 16000 वार्षिक व अन्य से आय 12000 वार्षिक होता था। जिससे वे अपना परिवार का पालन पोषण करने व बच्चो की शिक्षा में पूरा पैसा खर्च कर देते थे।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में सी.आर.पी. राउण्ड पर आये दीदीयों के द्वारा बिहान योजना के बारे में पूर्ण जानकारी दी गई। जिससे मैं भी समूह में जुड़ने के लिए इच्छा जाहिर की और मुझे गौरी महिला स्वयं सहायता समूह में सदस्य के रूप में जोड़ा गया। मैं स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद सी.आई.एफ. के रूप में 50000 रुपए एवं बैंक लिंकेज के रूप में 100000 रुपए लेकर मेरे द्वारा कृषि के साथ-साथ किराना दुकान किया गया और किराना प्रति दिवस 4600 का बिक्री हो जाता है। जिसमें मुझे प्रति दिवस 450 प्रति दिवस आय होता है। इस प्रकार समूह से जुड़ कर समूह की महिलाएं आजीविका गतिविधि अपनाकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रही है। जिससे मैं अपने परिवार को अच्छे से चला पा रही हूं। अब वह अपने को आत्मनिर्भर एवं सशक्त महसूस कर रही है।

एक नजर

डॉ. अंबेडकर जयंती पर यूनियन बैंक संघटना कार्यालय का हुआ शुभारंभ

अनिल/हरियाणाः युनियन बँक एससी एसटी कर्मचारी कल्याण संघटना। पुणे झोन युनिटच्या कार्यालयाचे उद्घाटन भारतरत्न डॉ। बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 135 व्या जयंतीच्या निमित्त त्यांना अभिवादन पर माननीय किरणजी अल्हाट बहुजन समाज पार्टी-महाराष्ट्र महासचिव यांच्या हस्ते करण्यात आले। त्याप्रसंगी पुणे शहराचे अध्यक्ष राहुल जी कांबळे, पुणे जिल्हा प्रभारी किरणजी गाडे, पुणे जिल्हा सदस्य भोलारामजी जयस्वाल उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संयोजन माननीय रुपेश जी नागमोडे साहेब युनियन बँक ऑफ इंडिया यांनी केले होते।

वाहन चोर हुआ गिरफ्तार, ब्रेजा कार व फर्जी कागजात हुए बरामद

राकेश कुमार शर्मा/उत्तर प्रदेशः जनपद सहारनपुर के थाना नकुड़,सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से चोरी की 01 ब्रेजा कार, 01 फर्जी नम्बर प्लेट तथा 01 कूटरचित आर.सी (प्रपत्र) बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अफराध नियंत्रण, चोरी,लूट,डकैती,वाहन चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्ताही हेतु लगातार गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष नकुड़ श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 11.04.2026 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 01 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त जीशान पुत्र रिजवान बेग निवासी मौ0 संजय विहार कस्बा बनत थाना आर्दश मण्डी जिला शामली को नकुड-गंगोह रोड पर बिजलीघर अम्बेहटा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 ब्रेजा कार, 01 फर्जी नम्बर प्लेट तथा कूटरचित आरसी बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 207/26 धारा 317(5),318(4),336(2),338,336(3),340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

'राष्ट्रीय माता' घोषित करने की मांग को लेकर न्याय एवं अधिकार समिति का अभियान तेज

सोजित्रा आशाबेन

गुजरातः गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग करते हुए न्याय एवं अधिकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्री परसोतमभाई एन. मुंगरा ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी जी, राष्ट्रपति महोदय, केंद्रीय गृहमंत्री जी, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल जी, गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, प्रत्येक जिले के कलेक्टरों, कमिश्नर, तालुका एवं जिला प्रमुखों, पदाधिकारियों, सदस्यों, ग्राम पंचायत के सरपंचों, ग्राम पंचायत के सदस्यों, धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, विभिन्न संगठनों के अध्यक्षों, सामाजिक अग्रणियों, सामाजिक कार्यकताओं, पाटीदार नेताओं,

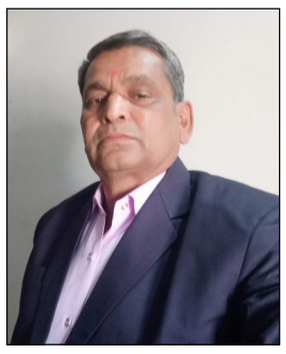

सभी समाजों के अग्रणियों, मीडिया कर्मियों, पत्रकार मित्रों, पुलिस कर्मियों, देश के साधु-संतों, महंतों, उच्च पदस्थ अधिकारियों तथा गुजरात और देश के नागरिकों से अपील की है कि वे सभी मिलकर, साथ ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि संगठनों के वास्तविक अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए, भारत में गाय माता की हो रही हत्या को पूरी तरह बंद करने के लिए उच्च स्तर पर प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को तथा जिला स्तर पर कलेक्टर, कमिश्नर, महानगरपालिका और पुलिस आयुक्त आदि को लिखित रूप में ज्ञापन देंगे।

देश में प्रतिदिन हजारों-हजार गायों का वध हो रहा है। हजारों गौवंश की हत्या हो रही है। इसे पूर्णतः बंद करने के लिए जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। भारत के किसानों और मालधारियों से विनम्र निवेदन है कि वे अपनी गाय माता और गौवंश को कत्लखाने में न भेजें और इस पाप के भागीदार न बनें। यदि गायों के वध को नहीं रोका गया, तो आने वाले दस वर्षों में गाय माता इस धरती पर दिखाई नहीं देगी। सभी गौ-प्रेमियों से अनुरोध है कि वे इस अभियान से जुड़कर गाय माता की रक्षा करें और उन्हें राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाएं। गाय माता के शरीर में सूर्य नाड़ी होने का उल्लेख किया गया है, जो अन्य किसी में नहीं होती। अनेक रोगों में गाय का दूध, घी, गोमूत्र आदि उपयोगी और पवित्र माने जाते हैं। इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैनर लगाए जाएंगे। यह एक सामाजिक और पुण्य कार्य है।

गाय माता की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसलिए यहां गाय का वध नहीं होना चाहिए। इस कार्य में सभी से सहयोग और समर्थन देने की अपील करते हुए, प्रदेश अध्यक्ष श्री परसोतमभाई एन. मुंगरा (न्याय एवं अधिकार समिति, गुजरात) ने कहा कि हम सभी मिलकर गाय को 'राष्ट्र माता' का दर्जा।

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

राकेश कुमार शर्मा

उत्तर प्रदेशः वादी की दाखिला तहरीर बावत प्रतिवादी विक्की उर्फ विकास पुत्र राकेश निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री उम्र करीब 08 के साथ घर मे घुसकर छेडछाड करने के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 139/26 धारा 75(2)/333/115(2)/352/351(2) बीएनएस व 09एम/10 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना के तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पर पंजीकृत 139/26 धारा 75(2)/333/115(2)/352/351(2) बीएनएस व 09एम/10 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त विक्की उर्फ विकास पुत्र राकेश निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर को भोगपुर पुलिया से गिरफ्तार किया गया।

नामित सभासदों का शपथ ग्रहण, भव्य स्वागत के साथ समारोह सम्पन्न

गौरव कुमार

उत्तर प्रदेशः कस्बा झिंझाना नगर पंचायत कार्यालय परिसर में शुक्रवार दिनांक 10 अप्रैल,उत्तर प्रदेश सरकार के दिशानिर्देशन में चयनित तीन सभासदों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में आयोजन के दौरान तीनों नवनियुक्त चयनित सभासदों रवि गहलौत, अरविंद बंसल व पवन खटीक का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शामली माननीय रामजीलाल कश्यप, जिला मंत्री श्रीपाल एस डी एस स्कूल प्रबंधक व भाजपा नेता रमेश गोड पिंकी/संजू सभासद, संजय कश्यप आदि शामिल हुए, नगर पंचायत चैयरमैन सुरेश पाल कश्यप एंव अधिशासी अधिकारी समीर कश्यप ने शपथ ग्रहण

समारोह के मौके पर नव चयनित सभासद गणों का स्वागत कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी,और अपील की कि तीनों सभासद जनता के प्रति अपनी निष्ठा को कायम रखें तथा ईमानदारी के साथ जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर कार्य कर नगर में अपना योगदान प्रदान करें। जिससे नगर पंचायत कार्यालय का नाम रोशन हो और आपकी ख्याति नगर में विस्तृत हो सके।

भाजपाई जिलाध्यक्ष शामली माननीय रामजीलाल ने तीनों नामित सभासदों से अपीलीय शब्दों में उपस्थित लोगों के समक्ष कहा कि सरकार द्वारा संचालित जनहित में योजनाओं को धरातल पर पात्रों तक पहुंचाने में पूर्णतया सहयोग प्रदान करें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास एंव सबका विश्वास के अनुसार कार्य कर रही है। शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में अनेक गणमान्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए सबने जनता के हित में कार्य करने का आह्वान किया और नवनियुक्त सभासदों का हार्दिक स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। शपथ ग्रहण समारोह हर्षोल्लास व धूमधाम से सम्पन्न हुआ, नवनियुक्त सभासदों का भव्य स्वागत किया गया और गलियों, बाजारों तथा उनके आवासों पर भी उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की गई। नगर पंचायत कार्यालय परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के उपरांत नवनियुक्त सभासद रवि गहलोत का मौहल्ला माजरा वार्ड संख्या एक में भी हार्दिक अभिनन्दन के साथ उनके आवास पर धूमधाम व हर्षोल्लास से उनका जोरदार स्वागत किया गया,इस हर्ष उल्लास के मौके पर उनके परिवार सहित जिलाध्यक्ष भाजपाई रामजीलाल कश्यप, गणमान्य नागरिक आन्नद चंचल प्रधान वाल्मीकिन समाज, विनोद सौदाई, नितिन सौदाई, गौतम चुनयाना, जुगनू सौदाई, रमन गहलौत, पप्पू गहलौत, भाजपा नेता नवीन कुमार, अरूणा गहलोत, माता श्री लोकेश देवी, विमल सौदाई, प्रदीप घावरी, शरद पाहिवाल, नीरज चौहान, तनू गहलौत, आशा देवी, गुनगुन गहलौत, पीहू गहलौत, कुंज सौदाई, साहिल सौदाई व सौरभ सौदाई सहित आदि लोग उपस्थित रहे।

महाराष्ट्र में नकली पनीर Analogue Paneer पर हुई सख्ती, जांच के दिए गए दिशा निर्देश

ज्ञानेंद्र बहादुर सिंह

उत्तर प्रदेशः कली पनीर (Analogue Paneer) की समस्या को लेकर प्रशासन और सरकार काफी सख्त हो गई है। विधानसभा में उठाई गई आवाजों के अनुसार, बाजार और होटलों में वनस्पति तेल, केमिकल और स्टार्च से बना नकली पनीर बेचा जा रहा है। महाराष्ट्र पनीर खबरी (नवीनतम अपडेट): सख्ती और छापेमारीः खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने मुंबई और आसपास के इलाकों में छापे मारकर सैकड़ों किलो

नकली पनीर नष्ट किया है। **विधानसभा में मुद्दाः** भाजपा विधायक विक्रम पाचपुते ने मार्च 2025 में विधानसभा में नकली पनीर का पैकेट लेकर यह मामला उठाया, जिसमें मिलावटी पनीर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। एनालॉग पनीर पर चेतावनीः होटल, रेस्टोरेंट और दुकानदारों को अब यह स्पष्ट करना होगा कि वे असली पनीर बेच रहे हैं या वनस्पति तेल से बना 'एनालॉग पनीर'। स्वास्थ्य के लिए खतराः यह नकली पनीर केमिकल और पाम ऑयल से बनता है, जिससे कैंसर और किडनी खराब होने का खतरा है। कैसे पहचानें? असली पनीर जलने पर राख बनता है, जबकि नकली पनीर प्लास्टिक की तरह पिघलता है। साथ ही, असली पनीर पानी में डूब जाता है, जबकि नकली तैरता है। डेयरी उद्योग की मांगः महाराष्ट्र के डेयरी उद्योग ने एनालॉग पनीर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की है, क्योंकि इससे असली दूध से बने पनीर की बिक्री पर असर पड़ रहा है।

राजगढ़ में दो आचार्यों का भव्य नगर प्रवेश, 21 अप्रैल को मोहनखेड़ा तक निकलेगा पैदल संघ

अशोक भंडारी

उत्तर प्रदेशः परम पूज्य राष्ट्रसंत गच्छाधिपती आचार्य देवेश श्रीमद् विजय लेखेंद्र सुरिश्वरजी महाराज साहब एवं परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य देवेश श्रीमद् विजय हितेशचंद्र सुरिश्वरजी महाराज साहब आदि मुनी मंडल एवं साध्वी मंडल का गुरु पुण्य भूमि राजगढ़ नगर मैं भव्य नगर प्रवेश नगर प्रवेश हुआ ।नवकारसी के पश्चात शिव वाटिका से चल समारोह प्रारंभ हुआ जो नगर के प्रमुख मार्गो से होता हुआ राजेंद्र भवन पहुंचा जहां दोनों आचार्य श्री के मंगल प्रवचन हुए उसके पश्चात सकल श्री संघ राजगढ़ की ओर से दोनों आचार्य को कामली औड़ाई गई ।कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर आरके जैन एवं दीपक जैन ने किया तथा अशोक भंडारी ने आभार व्यक्त किया ।इस अवसर पर नवकारसी के लाभार्थी परिवार

का बहुमान भी किया गया। दूसरे दिन जय तलेटी से दोनों आचार्य ,मुनी मंडल एवं साध्वी मंडल का मोहनखेड़ा तीर्थ के लिए भव्य एवं ऐतिहासिक प्रवेश हुआ ,पार्वती गार्डन में नवकारसी के पश्चात विशाल चल समारोह प्रारंभ हुआ ।रास्ते में मुनी जयप्रभविजय जी के मंदिर में दर्शन वंदन किये उसके पश्चात जयंत सेन म्यूजियम में विराजित परम पूज्य गच्छाधीपती आचार्य नित्यसेन सुरिश्वरजी महाराज साहब के के दर्शन वंदन किये ।इस ऐतिहासिक पल के अनेक गुरु भक्त साक्षी बने जब तीन आचार्यो ,

साधु मंडल एवं साध्वी मंडल का मिलन हुआ ।वहां से चल समारोह मोहनखेड़ा तीर्थ पहुंचा जहां पर तीर्थ ट्रस्ट की ओर से आचार्य श्री की गहुली की गई एवं अगवानी की गई ।सभी ने मंदिर में दर्शन वंदन किये उसके पश्चात धर्म सभा हुई जिसमें आचार्य भगवंतो के प्रवचन हुए ।इस अवसर पर मोहनखेड़ा तीर्थ ट्रस्ट मंडल के अलावा अनेक गणमान्य नागरिक ,समाजसेवी तथा बाहर से पधारे अनेक श्रीसंघों के सदस्य उपस्थित थे ।दिनांक 21 अप्रैल 24 ,मंगलवार को दोनों आचार्यो की निश्रा में अशोक राजमल जी भंडारी परिवार की ओर से उनके निवास से राजगढ़ से मोहनखेड़ा के लिए पैदल यात्री संघ का भी आयोजन रखा गया है ।

जिसमें श्री अभिधान राजेंद्र कोष को लेकर परिवारजन रथ में बैठेंगे ।यात्री संघ मंडी गेट से प्रारंभ होगा जो नगर के विभिन्न मार्गो से होता हुआ मोहनखेड़ा तीर्थ पहुंचेगा जहां प्रवचन के पश्चात सुमेतिलालजी सराफ परिवार की ओर से स्वामीवात्सल्य का आयोजन भी रखा गया है । समाजसेवी एवं पत्रकार अशोक भंडारी ने सकल जैन श्री संघ राजगढ़ के सभी समाजजनों से स-परिवार अधिक से अधिक संख्या में इस पैदल यात्रा संघ में पधारने का निवेदन किया है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती पर भव्य आयोजन, अंबेडकर भवन निर्माण की मांग उठी

राधे श्याम गुर्जर

मध्य प्रदेशः भारत के संविधान निमार्ता, सामाजिक न्याय के अग्रदूत एवं महान विचारक डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मूंदी नगर के वार्ड क्रमांक 08 अंबेडकर वार्ड में भव्य एवं गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरा क्षेत्र बाबा साहेब के जयकारों और उत्साह से गूंज उठा। कार्यक्रम में मान्धाता विधानसभा क्षेत्र के विधायक नारायण पटेल, सांसद प्रतिनिधि चन्द्रमोहन राठौर,नगर परिषद मूंदी की अध्यक्ष श्रीमती ज्योति बाला राठौर,उपाध्यक्ष राजनारायण मंडलोई सहित बड़ी सख्या मे जनप्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 08 के पार्षद सखाराम निमोले ने मांग रखी कि वार्ड क्रमांक 08 में स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा स्थल पर एक सुविधायुक्त, आधुनिक एवं डबल

मंजिला अंबेडकर भवन का निर्माण कराया जाए।

उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि प्रस्तावित भवन सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा, जिससे क्षेत्रवासियों को बहुआयामी सुविधाएं प्राप्त होंगी और समाज में जागरूकता एवं एकता को बल मिलेगा। इसी दौरान क्रमांक 08 में पीपल के पेड़ से लखनलाल राठौर के मकान तक लगभग 15.66 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने, सामाजिक समानता को बढ़ावा देने तथा भाईचारे की भावना को सशक्त करने का संकल्प लिया। संपूर्ण आयोजन श्रद्धा, सम्मान और सामाजिक जागरूकता का प्रेरणादायी उदाहरण बनकर सामने आया। भारत के संविधान निर्माण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मजयंती के अवसर पर मंगलवार 14 अप्रेल को जिला एवं मुंदी नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा मुंदी मे उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह सहित बड़ी संख्या मे कांग्रेस कार्यकर्त्ता मौजूद रहे।

सहारनपुर स्मार्ट सिटी की रंगीनियों से जगमग, हसनपुर फव्वारा बना आकर्षण का केंद्र

घनश्याम दास

उत्तर प्रदेशः स्मार्ट सिटी सहारनपुर देखने लायक हो गयी है। सांझ ढलते ही सहारनपुर रंगीनियों से नहा उठता है। शहर के प्रमुख चौराहे, प्रमुख मार्ग, हसनपुर चौंक के चौराहे पर सुंदर फव्वारा, महानगर के पुल जब रंग-बिरंगे प्रकाश बिंदुओं से झिलमिलाते हैं तो सहारनपुर अपनी एक अनुपम छटा के साथ बहुत मनोहर नजर आता है। महापौर डॉक्टर अजय कुमार के मार्ग दर्शन और माननीय नगरायुक्त शिपू गिरि के निर्देश पर सहारनपुर महानगर को विशेष साफ-सफाई के साथ-साथ तिरंगा लाइटों, झिलमिलाती रंगीन लड़ियों से ऐसा सुंदर रुप दिया गया है जो हर किसी का मन मोह रहा है। शाम ढ़लते ही मुख्य मार्गो और चौराहों पर घूमते हुए शहर के लोग रंगीनियों का आनंद ले रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट रोड व अस्पताल रोड पुल, अम्बाला रोड

पुल तथा शारदा नगर पुलों पर भी तिरंगा लाइटों की निराली आभा दिखायी दे रही है। हसनपुर चौंक न केवल लाइटों के साथ बेजोड़ सुंदरता दिखा रहा है अपितु रंग-बिरंगा फव्वारा अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत कर रहा है।

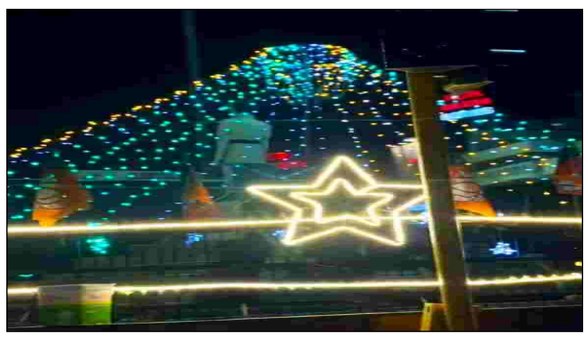

पथ प्रकाश प्रभारी वी बी सिंह ने बताया कि महानगर के पांच चौराहों घंटाघर, अग्रसैन चौंक, विश्वकर्मा चौंक, अम्बेडकर चौंक व चौधरी चरणसिंह चौंक को जहां विभिन्न प्रकार की लाइटों से सजाया गया है वहीं कोर्ट रोड से हसनपुर चुंगी तक, अग्रसेन चौंक से कचहरी पुल तक, स्टेशन से घंटाघर, जीपीओ से घंटाघर, घंटाघर से अम्बाला रोड पुल तथा देहरादून चौंक से नौगजा पीर तक सभी मार्गों को तिरंगा व गोल्डन लाइटों से सजाया गया है। कांवड़ रुट यानि देहरादून रोड पर न्योन लाइट लगवाई गयी हैं, जिसमें खंभों पर शंख,कलश व त्रिशूल आदि की सुंदरता देखते ही बनती हैं।

तारिक अनवर की अगुवाई में मनिहारी मजार शरीफ पर ऐतिहासिक चादरपोशी, अमन-शांति का संदेश

मोहम्मद फि रोज आलम

बिहारः मनिहारी मजार शरीफ में आयोजित पावन चादरपोशी कार्यक्रम न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि सामाजिक समरसता, प्रशासनिक संवेदनशीलता और जनप्रतिनिधियों की सकारात्मक भूमिका का एक प्रेरणादायक उदाहरण भी प्रस्तुत करता नजर आया।

इस गरिमामयी अवसर पर कटिहार के लोकप्रिय सांसद तारिक अनवर स्वयं उपस्थित रहे।

उनके साथ अनुमंडल प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के रऊट, रऊढड, रल्ढड सहित कई वरिष्ठ एवं जिम्मेदार पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता से यह आयोजन पूरी तरह सुव्यवस्थित, शांतिपूर्ण और अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम की शुरूआत

विधिवत दुआ-फातिहा और चादरपोशी के साथ की गई।

मजार शरीफ पर अकीदत के फूल चढ़ाए गए और अमन-चैन, भाईचारे, सामाजिक सौहार्द एवं क्षेत्र की खुशहाली की दुआ मांगी गई। इस अवसर पर सांसद तारिक अनवर ने कहा कि उर्स और चादरपोशी जैसे आयोजन हमारी साझा गंगा-जमुनी तहजीब की पहचान हैं, जो समाज को जोड़ने, दिलों को करीब लाने और इंसानियत के पैगाम को मजबूत करने का कार्य करते हैं।

प्रशासनिक पदाधिकारियों की सतत निगरानी और मुस्तैदी से श्रद्धालुओं में सुरक्षा और विश्वास का माहौल देखने को मिला। साफ-सफाई, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था एवं भीड़ नियंत्रण को लेकर प्रशासन की तैयारियां हर स्तर पर सराहनीय रहीं। यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ कि प्रशासन आमजन की आस्था, सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।

चादरपोशी कार्यक्रम के दौरान मनिहारी क्षेत्र में विशेष उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में अकीदतमंद मजार शरीफ पहुंचे और पूरे वातावरण में शांति, श्रद्धा एवं आपसी भाईचारे की भावना स्पष्ट रूप से झलकती रही।

कुल मिलाकर यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से ऐतिहासिक साबित हुआ, बल्कि प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय, विश्वास और सुशासन का सशक्त संदेश भी देकर गया।

शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न

प्रभेश मिश्रा

छत्तीसगढ़ः जिला संयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आज कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन की अध्यक्षता में शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आदिवासी विकास विभाग और शिक्षा विभाग की गतिविधियों की गहन समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

छात्रावास-आश्रम में शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने के निदेर्शः-

बैठक की शुरूआत आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा से हुई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आगामी शैक्षणिक सत्र में छात्रावास, आश्रम एवं कन्या शिक्षा परिसर में प्रवेश नियमानुसार

सुनिश्चित किया जाए तथा कोई भी सीट रिक्त न रहे। इसके लिए बेहतर कार्ययोजना बनाकर उसका शत-प्रतिशत क्रियान्वयन करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। इसके साथ ही देवगुड़ी एवं प्राधिकरण के अपूर्ण निर्माण कार्यों को अविलंब गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के भी निर्देश दिए गए।

नवाचार के रूप में लागू होगा ग्रेडिंग सिस्टमः-

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शिक्षा, परीक्षा परिणाम, अधोसंरचना की देखरेख एवं छात्रों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के आधार पर ग्रेडिंग सिस्टम को नवाचार के रूप में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण और उन्नत रहवासी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

सिविक सेंस और मध्यान्ह भोजन गुणवत्ता पर विशेष जोरः-

शिक्षा विभाग की समीक्षा में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु बेहतर सिविक सेंस विकसित करने पर जोर दिया गया। जिले के समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की आपार आईडी निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने समस्त बीईओ को निर्देश दिए कि शेष विद्यार्थियों के वांछित दस्तावेज शीघ्र पूर्ण कर आपार आईडी निर्माण का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए। मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई ताकि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े।

बैठक में आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त घनश्याम कुमार सिंह, सहायक संचालक रविंद्र सिंह, डीएमसी मनोज साहू, समस्त बीईओ तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

डोंडाइचा के अहिंसा इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल उषा मनोरे ने अर्थशास्त्र में पीएचडी पूरी की

देवेंद्र बद्रीलाल यादव

महाराष्ट्रः अहिंसा इंटरनेशनल स्कूल, डोंडाइचा की प्रिंसिपल, श्रीमती उषा मनोरे ने इकोनॉमिक्स में अपनी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (Ph.D.) की डिग्री सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। उनकी रिसर्च का टॉपिक है 'महाराष्ट्र में जिला परिषद स्कूलों में पब्लिक एजुकेशनल खर्च का इकोनॉमिक एनालिसिसः धुले जिले के खास रेफरेंस के साथ (2010-11 से 2020-21), और यह रिसर्च प्राइमरी एजुकेशन पर सरकारी खर्च की गहरी स्टडी पेश करती है। यह स्टडी पिछले एक दशक में पब्लिक एजुकेशनल खर्च के ट्रेंड्स, बनावट और असर की जांच करती

है। यह रिसर्च, टीचर्स, स्टूडेंट्स और जिला परिषद अधिकारियों की भागीदारी के साथ बड़े पैमाने पर फील्डवर्क पर आधारित है, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और असल एजुकेशनल नतीजों के बीच के अंतर को दिखाती है।

इस रिसर्च के नतीजे बहुत अहम हैं; क्योंकि वे पब्लिक फंड के सही इस्तेमाल, एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी और एजुकेशन सेक्टर में जरूरत के हिसाब से प्लानिंग की जरूरत पर जोर देते हैं। यह स्टडी गांव की शिक्षा की क्वालिटी सुधारने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और सभी को पढ़ाई के बराबर मौके देने के लिए प्रैक्टिकल सुझाव देती है; इस तरह, यह रिसर्च सामाजिक और एजुकेशनल विकास के बड़े लक्ष्यों में योगदान देती है। इस शुभ मौके पर, श्रीमती मनोरे ने भगवान के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए उनका दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने माता-पिता, करीबी परिवार और दोस्तों का भी दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनके पूरे सफर में हमेशा साथ दिया और हिम्मत दी।

शिक्षा सुविधाओं की कमी, TET परीक्षा में छात्रों को परेशानी

माहेश्वरी कांजीभाई नारणभाई

गुजरातः कच्छ जिला आज भी देश के उन क्षेत्रों में शामिल है, जहाँ शिक्षा और उच्च शिक्षण संस्थानों की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। हजारों छात्र-छात्राएँ आज भी विश्वविद्यालय और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी मूलभूत व्यवस्थाओं से वंचित हैं, जिसके कारण उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। हाल ही में आयोजित टीईटी (Teacher Eligibility Test) परीक्षा ने इस समस्या को और उजागर कर दिया। कच्छ से अहमदाबाद परीक्षा देने आने वाले हजारों परीक्षार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लंबी दूरी तय करके पहुँचने वाले इन युवाओं के लिए न तो उचित रहने की व्यवस्था थी और न ही भोजन या अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध थीं। कई परीक्षार्थियों को भूखे रहकर परीक्षा देनी पड़ी, तो कई को रातभर सफर कर थकान के बावजूद परीक्षा में बैठना पड़ा। स्थानीय युवाओं और अभिभावकों का कहना है कि इस तरह की परिस्थितियों में छात्रों के लिए अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना बेहद कठिन हो जाता है। उनका मानना है कि अगर कच्छ जिले में ही परीक्षा केंद्र और विश्वविद्यालय की बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ, तो छात्रों को इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

इस मुद्दे को लेकर अब लोगों में आक्रोश बढ़ता

जा रहा है। सामाजिक कार्यकताओं और स्थानीय संगठनों ने सरकार से मांग की है कि कच्छ जिले में स्थायी रूप से टीईटी जैसी परीक्षाओं के लिए केंद्र स्थापित किए जाएँ और उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्तर की सुविधाएँ विकसित की जाएँ। लोगों का कहना है कि कच्छ जैसे बड़े जिले को शिक्षा के क्षेत्र में नजरअंदाज करना उचित नहीं है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यहाँ के हजारों युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो सकता है।

हांसी पुलिस की मॉक ड्रिल, आपात हालात से निपटने का प्रशिक्षण

राममेहर

हरियाणाः पुलिस अधीक्षक हांसी श्री विनोद कुमार, आईपीएस के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जिला हांसी पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस लाइन हांसी में पुलिस जवानों के लिए एक व्यापक एवं सुनियोजित मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल को प्राकृतिक आपदा, भीड़ नियंत्रण, कानून-व्यवस्था की चुनौती, अपराध नियंत्रण एवं अन्य सुरक्षा संबंधी जोखिमों जैसी आपात परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार करना है। मॉक ड्रिल के दौरान जवानों को वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप अभ्यास करवाया गया, जिससे उनकी त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता, समन्वय, निर्णय लेने की क्षमता एवं कार्यकुशलता में

उल्लेखनीय वृद्धि हो सके। ड्रिल में विभिन्न परिदृश्यों के तहत त्वरित कार्रवाई, टीम वर्क, संचार प्रणाली के प्रभावी उपयोग तथा अनुशासन बनाए रखते हुए कार्य करने के व्यावहारिक तरीके विस्तार से सिखाए गए।

साथ ही, मौके पर अलग-अलग परिस्थितियों का अभ्यास करवाकर जवानों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया गया कि वे वास्तविक हालात में बिना घबराहट के प्रभावी ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। इस अवसर पर डीएसपी श्री देवेंद्र नैन, पुलिस लाइन प्रबंधक प्रदीप कुमार, मुख्य ड्रिल इंस्ट्रक्टर राजवीर सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। ड्रिल इंस्ट्रक्टर द्वारा जवानों को मॉक ड्रिल के तकनीकी पहलुओं, सुरक्षा मानकों एवं आपसी समन्वय के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा उन्हें हर परिस्थिति में सजग, अनुशासित एवं जिम्मेदार बने रहने के लिए प्रेरित किया गया।

मैहर में आग का कहर, राजा सुपर मार्केट में भीषण आग, लाखों का नुकसान

राधे श्याम गुर्जर

मध्य प्रदेशः मैहर। शहर के व्यस्त घंटाघर इलाके में मंगलवार शाम करीब 6 बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब राजा सुपर मार्केट में अचानक भीषण आग लग गई। पंजाबी गुरुद्वारे के पास स्थित इस दुकान से उठती तेज लपटों और घने धुएं ने कुछ ही देर में पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया।

आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई। आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और हर कोई सुरक्षित स्थान की ओर भागता नजर आया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू

पाया। समय रहते कार्रवाई होने से आग आसपास की अन्य दुकानों तक नहीं फैल सकी और एक बड़ा हादसा टल गया।

लाखों का सामान जलकर राख, जनहानि नहीं

इस भीषण आग में दुकान के अंदर रखा लाखों रुपये का सामान पूरी तरह नष्ट हो गया। हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल रहा और लोग सहमे हुए नजर आए। प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

सम्पादकीय

नए ऐतिहासिक मोड़ पर न्यायपालिका

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बीच हुआ संवाद न्यायिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कथित आबकारी घोटाला मामले में 21 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। मई से सितंबर 2024 के बीच उन्हें अंतरिम जमानत मिली और अंततः रिहाई हुई। लगभग दो साल बाद फरवरी 2026 में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों की कमी के कारण अरविंद केजरीवाल को तमाम आरोपों से बरी कर दिया। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई इस फैसले से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि अदालत ने सबूतों का सही मूल्यांकन नहीं किया, इसलिए उन्होंने इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। लेकिन हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के समक्ष मामला जाने से श्री केजरीवाल ने असंतोष दिखाया। अरविंद केजरीवाल अपनी पैरवी खुद कर रहे हैं और इस सोमवार उन्होंने जस्टिस शर्मा के सामने ही यह मांग रखी कि वे खुद को इस मुकदमे अलग करें।

अदालत में अरविंद केजरीवाल ने तर्क दिया कि जस्टिस शर्मा ने ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है जो भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों द्वारा आयोजित किए गए थे, जिससे उनके मन में न्याय मिलने को लेकर आशंका पैदा होती है कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलने का डर है। श्री केजरीवाल ने कहा कि कानून के अनुसार केवल 'पूर्वाग्रह की उचित आशंका' ही किसी जज के केस से हटने के लिए पर्याप्त आधार है। उन्होंने जज के 'रिक्यूजल' यानी खुद को मामले से अलग करने के सिद्धांत पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह जरूरी नहीं है कि कोई जज पक्षपाती हो, लेकिन अगर पार्टियों के मन में कोई वाजिब शक है तो यह रिक्यूजल का मामला बनता है।

इस बारे में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा, 'मैंने खुद को सुनवाई से अलग रखने यानी रिक्यूजल से जुड़े कानून के बारे में बहुत कुछ सीखा। मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे खुद को सुनवाई से अलग रखने के लिए कहा है। लेकिन मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सीखा। मुझे उम्मीद है कि मैं एक अच्छा फैसला दे पाऊंगी।'

अब गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने एक और नया हलफनामा अदालत में दाखिल किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के दोनों बच्चे केंद्रीय सरकारी पैनलों में हैं, यानी वरिष्ठ अधिवक्ता और मोदी सरकार के सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता के अधीन काम कर रहे हैं। तुषार मेहता उन्हें मामले सौंपते हैं। ऐसी स्थिति में माननीय जज के लिए तुषार मेहता के खिलाफ कोई आदेश पारित करना कठिन होगा। इसलिए अन्य कारणों के साथ-साथ, माननीय न्यायाधीश को इस मामले से स्वयं को अलग कर लेना चाहिए। हलफनामे में दावा किया गया है कि चूंकि केंद्र सरकार इस मामले में एक पक्ष है, इसलिए इससे निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है।

भारतीय पत्रकारिता को कलंकित करता गोदी मीडिया

निर्मल रानी

सत्ता की गुलामी करने में मदहोश देश का गोदी मीडिया तमाम अपमानों,जलालत,विरोध व आलोचनाओं के बावजूद अपनी प्रस्तुति,सामग्री व शब्दों के चयन के स्तर को दिन प्रतिदिन गिराता जा रहा है। हद तो यह है अपनी टी आर पी बढ़ाने के चक्कर में पाकिस्तान व अन्य देशों के अतिथियों को अपने साथ लाईव जोड़कर उनसे विवदित व बेतुके सवाल पूछकर उन्हें बदकलामी करने के लिये जानबूझकर उकसाया जाता है। ताकि वे तीखा जवाब दें जिससे बहस में गर्मी पैदा हो और बहस में असंसदीय व अभद्र शब्दों का इस्तेमाल हो। और इसी शोर शराबे की आड़ में उनकी टी आर पी भी बढ़े उनका एजेंडा भी पूरा हो और उनके सरपरस्त आका भी खुश हो सकें। देश को कलंकित करने वाले ऐसे अनेक टी वी स्टूडियो में डिबेट के दौरान गाली गलौज,धक्का मुक्की मार पीट सब कुछ तो होता रहता है ? अफसोस यह कि यह सब पूर्वनियोजित होता है और जानबूझकर करवाया जाता है।

सरकारी टी वी चैनल डीडी न्यूज के शो दो टूक के एंकर अशोक श्रीवास्तव द्वारा अपने इसी शो में पिछले दिनों की गयी एक अत्यंत घटिया टिप्पणी को सुनकर भला कौन कह सकता कि यह भाषा किसी पत्रकार या टीवी एंकर की भाषा हो सकती है। एक लाइव डिबेट के दौरान अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि ह्वराहुल गांधी सावरकर के चप्पल की धूल के एक कण के हजारवें हिस्से के बराबर भी नहीं हैं। राहुल गांधी सावरकर के जूते की नोक के बराबर भी नहीं हैं, और उस नोक पर लगी धूल के कण के भी हजारवें भाग के बराबर नहीं हैं।ह्व एंकर अशोक श्रीवास्तव द्वारा यह टिप्पणी सावरकर को श्रद्धांजलि देते समय राहुल गांधी से उनकी तुलना करने के बहाने से की गई थी। इस ओछी व घटिया टिप्पणी के बाद खासकर कांग्रेस कार्यकताओं में उबाल आ गया। कई विपक्षी नेताओं ने भी ऐसी घटिया टिप्पणी को अपमानजनक व असभ्य बताया। इसके बाद युवा कांग्रेस कार्यकताओं ने नई दिल्ली में दूरदर्शन मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ये पत्रकारिता नहीं, सत्ता की दलाली है जैसे नारे लगाये। गोदी मीडिया का पुतला फूंका गया। इसके बाद यह सवाल भी खड़ा हुआ कि निजी टी वी चैनल तो भय लालच व्यवसायिकता अथवा वैचारिक कारणों से तो सत्ता की गोद में जाकर बैठ ही चुके हैं परन्तु आखिर देश के कर दाताओं के पैसों से चलने वाला सरकारी चैनल भी क्या अपनी निष्पक्षता खो चुका है ? क्या ऊ्रठी६२ पर भी करोड़ों रुपए लेने वाले पत्रकार व टाई सूट में सजे धजे टी वी ऐंकर भी अब आई टी सेल या ट्रोलर्स की भाषा बोलने के लिये मजबूर हो चुके हैं ?

इसी तरह एक निजी टीवी चैनल की एक एंकर हैं जिन्होंने पिछले दिनों इफ़्तार पार्टी आयोजित कर कई राजनेताओं को दावत दी थी। उनकी यह दावत और आमंत्रित लोगों को देखकर यह समझने में देर नहीं लगी कि उनका राजनैतिक रुझान भी है और वह पत्रकारिता के बाद संभवतः राजनीति में ही अपना कैरियर बना सकती हैं। दरअसल गोदी पत्रकारों को यह मालूम है कि गोदी से उतरने के बाद वे इस लायक ही नहीं रहेंगे कि अपना कोई प्लेटफॉर्म खड़ाकर उसपर अपने जौहर दिखा सकें। क्योंकि हर पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन,रवीश कुमार,अजीत अंजुम,अभिसार शर्मा,अशोक पाण्डेय,पुण्य प्रसून वाजपेई, प्रज्ञा मिश्रा,आरिफा खानम या आशुतोष जैसे पत्रकारों के नक़्शे कदम पर नहीं चल सकता। दरअसल ऐसी पत्रकारिता के लिये अध्ययन,साहस,ज्ञान,पत्रकारिता का दायित्वबोध आदि सब कुछ चाहिये जो चाटुकारिता या सत्ता की दलाली के लिये जरूरी नहीं। बहरहाल गोदी चैनल की यही मोहतरमा अपने चैनल पर एक पाकिस्तानी मेहमान को बार बार बुलाती हैं। यह जब उससे कोई तीखा सवाल जानबूझकर करती हैं तो वह शख़्स इनसे भी तीखा जवाब देता है। मैंने उसे अपशब्द बोलते,गलियां निकालते भी सुना यहाँ तक कि उसकी कई टिप्पणियों से हमारे देश की तौहीन भी हुई। परन्तु यह आज भी उसे जानबूझकर बार बार बुलाती हैं। अब तो उस पाकिस्तानी व्यक्ति की लोकप्रियता गोदी चैनल्स में इतनी बढ़ गयी है कि वह व्यक्ति दूसरे चैनल्स पर भी नजर आने लगा है। वह खुद भी कह चुका है कि तुम हिंदुस्तानी चैनल वाले मुझे बुलाते ही इसलिये हो ताकि तुम्हारी टी आर पी बढ़े ।

सनसनी फैलाने,पक्षपात करने,सत्ता का गुणगान करने,भ्रामक रिपोर्टिंग करने,बहस में अपना एजेंडा थोपने,साम्प्रदायिकता फैलाने सत्ता के बजाय विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने,मंहगाई,बेरोजगारी,शिक्षा,स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बहस न करने व इन मूल मुद्दों को न उठाने जैसी अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों के चलते आज विदेशों में भी भारतीय मीडिया की छवि नकारात्मक बन चुकी है। इसीलिये भारतीय मीडिया को अक्सर सरकार का चमचा या गोदी मीडिया कहकर संबोधित करते हैं।

बिहार में संभावनाएं विकास की: अब सत्ता सम्राट की

-ललित गर्ग-

> सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री के रूप में चयन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। वे कोई अप्रत्याशित या अपरिचित चेहरा नहीं हैं। बिहार की राजनीति में सक्रिय रहते हुए, उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए और विभिन्न राजनीतिक धाराओं से गुजरते हुए उन्होंने राज्य की जटिलताओं को निकट से समझा है। उनकी राजनीतिक यात्रा उन्हें एक व्यावहारिक नेता के रूप में स्थापित करती है, जो केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन की वास्तविकताओं से भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि उनके नेतृत्व से बिहार की जनता को एक ऐसे प्रशासन की उम्मीद है जो नीतिगत स्पष्टता के साथ-साथ क्रियान्वयन की क्षमता भी रखता हो।

बिहार की राजनीति लंबे समय से बदलाव, प्रयोग और नेतृत्व के उतार-चढ़ाव का साक्षी रही है। ऐसे परिदृश्य में जब लंबे इंतजार और जटिल कूटनीतिक समीकरणों के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शासन स्थापित होने की स्थिति बनती है और सम्राट चौधरी जैसे नेता मुख्यमंत्री के रूप में उभरते हैं, तो यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक संभावित राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तन का संकेत भी है। यह क्षण बिहार के लिए एक नए युग की शुरूआत के रूप में देखा जा रहा है, जहां अपेक्षाएं केवल शासन परिवर्तन की नहीं, बल्कि शासन की गुणवत्ता, दृष्टि और परिणामों की भी हैं। नये मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के सामने न सिर्फ बिहार की जनता में एक कुशल प्रशासक की छाप छोड़ने की चुनौती है, बल्कि पार्टी की अपेक्षाओं एवं नीतीश कुमार द्वारा खींची रेखाओं से आगे निकलने के संघर्ष में भी उन्हें खरा उतरना होगा। सम्राट को उससे आगे ऐसा कुछ करना होगा, ताकि भाजपा उसके आधार पर भविष्य की दावेदारी पेश कर सके एवं अपने बल पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की पात्रता विकसित कर सके। बिहार में भाजपा का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, सम्राट के भरोसे से।

सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री के रूप में चयन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। वे कोई अप्रत्याशित या अपरिचित चेहरा नहीं हैं। बिहार की राजनीति में सक्रिय रहते हुए, उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए और विभिन्न राजनीतिक धाराओं से गुजरते हुए उन्होंने राज्य की जटिलताओं को निकट से समझा है। उनकी राजनीतिक यात्रा उन्हें एक व्यावहारिक नेता के रूप में स्थापित करती है, जो केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन की वास्तविकताओं से भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि उनके नेतृत्व से बिहार की जनता को एक ऐसे प्रशासन की उम्मीद है जो नीतिगत स्पष्टता के साथ-साथ क्रियान्वयन की क्षमता भी रखता हो। किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि बिहार में नेतृत्व का मूल्यांकन केवल व्यक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी नीतियों, प्राथमिकताओं और परिणामों के आधार पर होता है। पिछले वर्षों में यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से सामने आई है कि शासन की सफलता का निर्धारण केवल मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व से नहीं, बल्कि उस व्यापक नीति-ढांचे से होता है जो केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करता है। भारतीय राजनीति में यह एक नया आयाम है, जहां केंद्र सरकार की नीतियां राज्यों के विकास की दिशा को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों के उदाहरण इस बात को पुष्ट करते हैं कि अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरों के बावजूद विकास की गति तेज रह सकती है, यदि नीतिगत समर्थन और प्रशासनिक इच्छाशक्ति मजबूत हो।

बिहार के संदर्भ में यह पहलू और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह राज्य लंबे समय तक अवसंरचनात्मक पिछड़ेपन, बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक विषमताओं से जूझता रहा है। ऐसे में सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वे इन जटिल समस्याओं के समाधान के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करें। केवल राजनीतिक स्थिरता पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि उसे विकासात्मक स्थिरता में परिवर्तित करना होगा। सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत क्षेत्रों में निरंतर सुधार के साथ-साथ रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि बिहार के युवाओं को अपने ही राज्य में अवसर मिल सकें। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बिहार के हालिया इतिहास में यदि किसी नेता ने प्रशासनिक सुधार और सुशासन की एक स्पष्ट छवि प्रस्तुत की है, तो वह नीतीश कुमार हैं। उन्होंने जिस समय सत्ता संभाली, उस समय बिहार ह्वजंगलराजह्व की छवि से जूझ रहा था। कानून-व्यवस्था की स्थिति दयनीय थी, अवसंरचना लगभग ध्वस्त थी और राज्य की छवि राष्ट्रीय स्तर पर नकारात्मक थी। ऐसे समय में नीतीश कुमार ने सड़क, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए। विशेष रूप से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइकिल योजना जैसी पहलें सामाजिक परिवर्तन का आधार बनीं। उन्होंने प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे शासन के प्रति जनता का विश्वास पुनः स्थापित हुआ।

नीतीश कुमार का व्यक्तित्व एक संतुलित, संयमित और व्यावहारिक नेता के रूप में उभरता है। वे आक्रामक राजनीति के बजाय संवाद और सहमति की राजनीति के पक्षधर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने राजनीति को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर उठाकर विकास के एजेंडे से जोड़ने का प्रयास किया। हालांकि समय के साथ उनकी राजनीतिक रणनीतियों और गठबंधनों में बदलाव ने उनकी छवि को कुछ हद तक प्रभावित भी किया, लेकिन उनके द्वारा स्थापित प्रशासनिक मानक आज भी बिहार के लिए एक संदर्भ बिंदु बने हुए हैं। सम्राट चौधरी के लिए यह एक बड़ी चुनौती और अवसर दोनों है कि वे इन स्थापित मानकों को न केवल बनाए रखें, बल्कि उन्हें और आगे बढ़ाएं। उन्हें यह समझना होगा कि बिहार की जनता अब केवल वादों से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि परिणाम चाहती है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी सुधार की व्यापक संभावनाएं हैं। सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता, उच्च शिक्षा के अवसर, अस्पतालों की स्थिति और चिकित्सकीय सुविधाओं का विस्तार ऐसे क्षेत्र हैं जहां ठोस कार्य की आवश्यकता है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जो किसी भी विकासात्मक प्रयास को कमजोर कर सकती है। यदि सम्राट चौधरी वास्तव में एक प्रभावी और जनोन्मुखी शासन स्थापित करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचारमुक्त शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। डिजिटल गवर्नेंस, ई-टेंडरिंग और निगरानी तंत्र को सशक्त बनाकर इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं।

महिला सशक्तिकरण भी बिहार के विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम है। पिछले वर्षों में इस दिशा में कुछ सकारात्मक पहलें हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। यदि सम्राट चौधरी इस क्षेत्र में ठोस और नवाचारी कदम उठाते हैं, तो यह बिहार की प्रगति को एक नई दिशा दे सकता है। पलायन की समस्या भी बिहार के लिए एक स्थायी चुनौती रही है। लाखों लोग रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में जाते हैं, जिससे न केवल राज्य की श्रमशक्ति का क्षरण होता है, बल्कि सामाजिक संरचना पर भी प्रभाव पड़ता है। इस समस्या का समाधान केवल उद्योगों के विकास और स्थानीय रोजगार के अवसरों के सृजन से ही संभव है। कृषि आधारित उद्योग, लघु और मध्यम उद्योग तथा स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देकर इस दिशा में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। निश्चिततौर पर यह कहा जा सकता है कि बिहार आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां अतीत के अनुभव, वर्तमान की अपेक्षाएं और भविष्य की संभावनाएं एक साथ उपस्थित हैं। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह राज्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यह उनके निर्णयों, नीतियों और कार्यशैली पर निर्भर करेगा। यदि वे नीतीश कुमार द्वारा स्थापित सुशासन के मानकों को आधार बनाते हुए नवाचार और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं, तो बिहार न केवल अपने पुराने कलंक से पूरी तरह मुक्त हो सकता है, बल्कि एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में भी उभर सकता है।

भारत में नोएडा से औद्योगिक अशांति, दिल्ली-एनसीआर के कई राज्यों में फैली

डॉ. ज्ञान पाठक

नोएडा के फेज-2 में प्रदर्शन हिंसक हो गया, और एक पुलिस वैन और दूसरी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जहां कई औद्योगिक इकाइयों के कामगार दोपहर के आसपास वेतन बढ़ाने और दूसरे फायदों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद विरोध प्रदर्शन नोएडा के दूसरे हिस्सों में फैल गये। प्रदर्शन की वजह से सुबह से ही ट्रैफिक पर असर पड़ा है।

जैसे-जैसे भारत सरकार धीरे-धीरे नयी श्रम संहिताओं के नियमों को लागू कर रही है, भारतीय कामगारों में तनाव बढ़ता जा रहा है। सरकार ने 1 अप्रैल, 2026 से इसे पूरी तरह लागू करने के अपने इरादे की घोषणा की थी, और अब 13 अप्रैल, 2026 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में औद्योगिक अशांति शुरू हो गई, जो शीघ्र ही दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में फैल गई, जिसमें हरियाणा के फरीदाबाद और मानेसर (गुरुग्राम), राजस्थान के भिवाड़ी, दिल्ली और कई दूसरी जगहें शामिल हैं। औद्योगिक इलाकों में न सिर्फ न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे मजदूरों ने सड़कें जाम कीं, बल्कि हिंसा, गाड़ियों में आग लगाना, पुलिस के साथ झड़प, पत्थरबाजी, फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की। उसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती भी हुई, जिन्होंने कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए लाठीचार्ज और बल का भी इस्तेमाल किया। पुलिस ने कहा कि वह स्थिति को काबू में रखने के लिए कम से कम बल का इस्तेमाल कर रही है।

नोएडा में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के बाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मजदूरों को भड़काने की कोशिश कर रहे 'असामाजिक' तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सचेत किया है कि लोगों को 'लगभग खत्म हो चुके नक्सलवाद को फिर से जिंदा करने की साजिश' से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, 'मजदूरों के नाम पर उपद्रव करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और औद्योगिक इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए।' राज्य के श्रम विभाग को स्थानीय अधिकारियों और औद्योगिक इकाइयों से बातचीत करने के लिए कहा गया है।

हालांकि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि हर मजदूर को सम्मानजनक वेतन, काम करने का सुरक्षित माहौल और मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों से श्रम कानूनों का पालन करने और मजदूरों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुलझाने के लिए कहा।

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि पुलिस उन लोगों की पहचान कर रही है जिन्होंने नोएडा में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर हिंसा भड़काई थी, और चेतावनी दी कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अशांति में शामिल 'भड़काऊ तत्वों' और 'बाहरी तत्वों' का पता लगाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश एटीएस ने फैक्टरी कामगारों के विरोध प्रदर्शन से संभावित घुसपैठ के सूत्रों की जांच शुरू कर दी है। एटीएस यह जांच कर रही है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान आगजनी का तरीका, खासकर जिस तरह से गाड़ियों में आग लगाई गई, क्या पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर अशांति भड़काने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीकों से मेल खाता है।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोएडा में कामगारों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए भाजपा सरकार की 'एकतरफा नीति' को जिम्मेदार ठहराया है, और आरोप लगाया है कि सरकार पूंजीपतियों का पक्ष लेती है जबकि वेतनभोगी कर्मचारियों और मजदूरों को नजरअंदाज करती है। उन्होंने कहा कि वेतन बढ़ाने को लेकर आंदोलन उन नीतियों की वजह से उग्र हो गया है जो 'पूंजीपतियों को बढ़ावा देती हैं लेकिन कामगारों का शोषण करती हैं'।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने स्थिति को ठीक से न संभालने के लिए सरकार की आलोचना की और कहा कि नोएडा में मदरसन कंपनी के बाहर के विजुअल 'परेशान करने वाले' थे। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, 'जब महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है और वेतन के नाम पर कामगारों का शोषण हो रहा है, तो युवा सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।' उन्होंने यह भी कहा, 'विज्ञापनों से खाली पेट नहीं भर सकते। आंसू गैस के गोले भूख मिटा नहीं सकते। वर्कर्स की जायज मांगों को नजरअंदाज करना बंद करें और दमन का सहारा लेने के बजाय हल निकालें।' ध्यान देने वाली बात यह है कि बेहतर वेतन के लिए आन्दोलन कर रहे मदरसन के सैंकड़ों कामगार फैक्टरी के अंदर घुस गए और वरिष्ठ अधिकारियों को वहां से बाहर नहीं जाने दे रहे थे।

नोएडा के फेज-2 में प्रदर्शन हिंसक हो गया, और एक पुलिस वैन और दूसरी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जहां कई औद्योगिक इकाइयों के कामगार दोपहर के आसपास वेतन बढ़ाने और दूसरे फायदों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।

महिला आरक्षण बिल के बाद बदलेगी संसद की सूरत

सौरभ वार्ष्णेय

१६ अप्रैल से संसद का विशेष संत्र आयोजित होने जा रहा है। इस सत्र में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। लंबे इंतजार और व्यापक राजनीतिक विमर्श के बाद पारित हुआ महिला आरक्षण बिल—जिसे आधिकारिक रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है—देश की संसद और विधानसभाओं की संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करता है, जो भारतीय राजनीति में लैंगिक संतुलन की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।

आज तक भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी सीमित रही है। हालांकि इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज और ममता बनर्जी जैसी प्रभावशाली महिला नेताओं ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन कुल संख्या के लिहाज से महिलाएं अब भी कम प्रतिनिधित्व वाली श्रेणी में रही हैं। ऐसे में यह आरक्षण बिल केवल संख्या बढ़ाने का नहीं, बल्कि नीति निर्माण में महिलाओं की दृष्टि और संवेदनशीलता को शामिल करने का प्रयास भी है।

इस विधेयक के लागू होने के बाद संसद की सूरत में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है। अधिक संख्या में महिला सांसदों की भागीदारी से सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और पोषण जैसे मुद्दों पर अधिक गंभीरता से चर्चा होने की संभावना है। इससे नीतियां अधिक समावेशी और जमीनी हकीकत के करीब बन सकती हैं।

हालांकि, इस बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी। राजनीतिक दलों को योग्य महिला उम्मीदवारों को तैयार करने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे। केवल आरक्षण से ही वास्तविक सशक्तिकरण संभव नहीं है; इसके लिए सामाजिक मानसिकता में बदलाव और राजनीतिक प्रशिक्षण भी उतना ही आवश्यक है।

इसके अलावा, आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी, जो इस कानून के क्रियान्वयन को प्रभावित कर सकती है। इस कारण, इसके प्रभावी लागू होने में समय लगने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।फिर भी, यह कहना गलत नहीं होगा कि महिला आरक्षण बिल भारतीय लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधिक, संतुलित और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह न केवल संसद की सूरत बदलेगा, बल्कि राजनीति की सोच और प्राथमिकताओं को भी नई दिशा देगा। यह विधेयक केवल महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि एक मजबूत, समावेशी और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की आधारशिला रखता है।

केंद्र सरकार ने हाल ही में उन आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया है, जो 2029 तक विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने के लिए प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों में उभर रही हैं। यह मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि संघीय ढांचे, प्रतिनिधित्व के संतुलन और लोकतांत्रिक विश्वास से भी जुड़ा हुआ है।महिला आरक्षण का उद्देश्य राजनीति में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। लंबे समय से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही है। ऐसे में 33त्न आरक्षण का प्रावधान एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ जुड़ा परिसीमन का सवाल कई जटिलताओं को जन्म देता है।

परिसीमन का अर्थ है जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। 2026 के बाद होने वाली संभावित परिसीमन प्रक्रिया में जनसंख्या के वर्तमान आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। यहीं से दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता शुरू होती है। इन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में जनसंख्या वृद्धि अधिक रही है। ऐसे में आशंका है कि परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों की सीटें घट सकती हैं, जिससे उनकी राजनीतिक ताकत कमजोर हो सकती है।

केंद्र सरकार का कहना है कि महिला आरक्षण और परिसीमन दो अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं, और किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि संतुलन और न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल आश्वासन से राज्यों की चिंताएँ दूर हो जाएंगी?

यह भी समझना जरूरी है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड? का प्रावधान क्यों रखा गया। इसका एक कारण यह है कि नए सिरे से सीटों का निर्धारण होने पर आरक्षित सीटों का संतुलित और न्यायसंगत वितरण संभव हो सके। लेकिन यही प्रावधान अब राजनीतिक विवाद का कारण बन रहा है।

समाधान के लिए आवश्यक है कि केंद्र और राज्यों के बीच संवाद और विश्वास कायम रखा जाए। एक ऐसा मॉडल विकसित किया जाए, जिसमें महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए क्षेत्रीय संतुलन भी बना रहे। संभव है कि परिसीमन के लिए केवल जनसंख्या ही नहीं, बल्कि अन्य मानकों को भी शामिल किया जाए, ताकि न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।महिला आरक्षण एक सामाजिक और लोकतांत्रिक आवश्यकता है, लेकिन इसे लागू करने की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी क्षेत्र या राज्य के साथ असमानता की भावना पैदा न करे। यह समय राजनीतिक परिपक्वता और दूरदर्शिता दिखाने का है, ताकि देश एक समावेशी और संतुलित लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ सके।

महिला आरक्षणः एक सामाजिक और लोकतांत्रिक आवश्यकता

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की अनिवार्यता है। लंबे समय से राजनीति और नीति-निर्माण के केंद्र में पुरुषों का वर्चस्व रहा है, जिसके कारण महिलाओं से जुड़े कई मुद्दे अपेक्षित प्राथमिकता नहीं पा सके। ऐसे में महिला आरक्षण का प्रश्न केवल प्रतिनिधित्व का नहीं, बल्कि बराबरी और सशक्तिकरण का भी है।महिलाएं देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी अभी भी सीमित है। पंचायत स्तर पर आरक्षण लागू होने के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि जब महिलाओं को अवसर मिलता है, तो वे न केवल प्रभावी नेतृत्व करती हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव भी लाती हैं। इस अनुभव को उच्च स्तर की राजनीति में लागू करना समय की मांग है।महिला आरक्षण सामाजिक असमानताओं को दूर करने का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है। भारतीय समाज में अब भी कई स्तरों पर लैंगिक भेदभाव मौजूद है, जो महिलाओं की प्रगति में बाधा बनता है। आरक्षण नीति उन्हें एक सशक्त मंच प्रदान करती है, जहां वे अपनी आवाज बुलंद कर सकती हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं।

लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व हो। यदि आधी आबादी निर्णय-निर्माण प्रक्रिया से बाहर रहती है, तो लोकतंत्र अधूरा ही रहेगा। महिला आरक्षण इस अधूरेपन को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।हालांकि, इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं, जैसे राजनीतिक दलों की इच्छाशक्ति, आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन और वास्तविक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद, महिला आरक्षण का महत्व कम नहीं होता। यह एक ऐसा कदम है जो भारत को अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और सशक्त लोकतंत्र की ओर अग्रसर कर सकता है। महिला आरक्षण केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के विकास के लिए आवश्यक है। यह न केवल समानता को बढ़ावा देता है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को भी मजबूत करता है।

पिछले दो वर्षों में अपराधों में 18.77 प्रतिशत की आई कमी - सीएम भजनलाल शर्मा

जयपुर, एजेंसी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस पर प्रदेश की कानून व्यवस्था की अहम जिम्मेदारी है। पुलिस द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाकर प्रदेश में आमजन को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस के जवान अथक परिश्रम, अनुशासन और जनसेवा के जज्बे के साथ हर परिस्थिति में ढाल बनकर प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है तथा हम अपराध मुक्त राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शर्मा गुरुवार को राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस ने 77 वर्षों की इस गौरवमयी यात्रा में साहस, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान की अनुपम मिसालें पेश की हैं। श्री शर्मा ने अमर शहीद पुलिसकर्मियों को नमन करते हुए कहा कि शहीदों ने आमजन की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। कम्युनिटी पुलिसिंग से साइबर अपराधों पर लगेगा अंकुश

नारावाड़ा ग्रिड में जंग लगे खंभों से बना हादसे का खतरा, ग्रामीणों में दहशत

गौतम कुमार/राजस्थान: जालौर जिले के नारावाड़ा गांव में स्थित बिजली का ग्रिड सब स्टेशन (GSS) इन दिनों बदहाली की हालत में है। यहां लगे बिजली के खंभे पूरी तरह जंग खा चुके हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग को इस समस्या के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जंग लगे खंभों के कारण बिजली सप्लाई भी प्रभावित हो रही है और आए दिन तकनीकी खराबियां सामने आ रही हैं।

ग्रामीणों में डर का माहौल

ग्रामीणों के अनुसार, बरसात या तेज हवा के समय ये खंभे कभी भी गिर सकते हैं, जिससे जान-माल का नुकसान हो सकता है। खासकर बच्चों और पशुओं के लिए यह खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक ग्रामीण ने बताया, "हमने कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ, तो बड़ा हादसा हो सकता है।" इस गंभीर मुद्दे पर अभी तक बिजली विभाग या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

पुलिस स्थापना दिवस पर सीएम ने लॉन्च किया पुलिस पेंशनर्स पोर्टल

अब घर बैठे मिलेंगी सुविधाएं

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान पुलिस गुरुवार को अपना 77वां स्थापना दिवस पूरे गौरव और उत्साह के साथ मना रही है। इस अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी में राज्यस्तरीय भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम स्थल पर आगमन बेहद आकर्षक रहा, जहां वे पुलिस की मोटरसाइकिल बटालियन और घुड़सवार जवानों के साथ समारोह स्थल तक पहुंचे। उन्होंने परेड की सलामी ली और प्रदेश के पुलिसकर्मियों के साहस, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा को नमन किया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए राजकॉप सिटीजन ऐप से जुड़े राजस्थान पुलिस पेंशनर्स पोर्टल का लोकार्पण किया। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के हजारों सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी और उनके परिजन अब घर बैठे डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इससे पेंशन संबंधी प्रक्रियाएं सरल व पारदर्शी बनेंगी और बुजुर्ग पेंशनर्स को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

स्थापना दिवस समारोह में इस वर्ष समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले तीन आम नागरिकों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सिरोही के प्रकाश प्रजापति, झालावाड़ के सुरजीत कश्यप और उदयपुर की बाल सुरक्षा सलाहकार सिंधु बिनुजीत को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कार्मिक) बीजू जॉर्ज जोसफ के निर्देशानुसार इन तीनों को उनके अनुकरणीय सामाजिक कार्यों के लिए चुना गया।

विशेष रूप से सिंधु बिनुजीत के कार्यों की सराहना की गई। उन्होंने वर्ष 2010 से डूंगरपुर के आदिवासी क्षेत्रों में बाल श्रम और पलायन रोकने के लिए यूनिसेफ के सहयोग से 'वत्सल वार्ता' और 'बाल मित्र थाने' जैसी पहल शुरू की। उनके प्रयासों से बच्चों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा और भय कम हुआ। वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इस मॉडल की सराहना करते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए थे। राज्यभर में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोटा, कोटपूतली, बांसवाड़ा और डूंगरपुर सहित कई जिलों में परेड, वृक्षारोपण, सम्मान समारोह और रक्तदान शिविरों का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिसकर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह आयोजन न केवल पुलिस बल के गौरवशाली इतिहास को याद करने का अवसर बना बल्कि समाज और पुलिस के बीच विश्वास को और मजबूत करने का संदेश भी देता है।

जनगणना 2027 के प्रथम चरण हेतु प्रगणकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण हुआ शुरू

प्रभेश मिश्रा

छत्तीसगढ़: सूरजपुर भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण - मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना - को सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के मार्गदर्शन तथा जिला जनगणना अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में सूरजपुर जिले के तहसील प्रतापुर चार्ज एवं तहसील ओडगी चार्ज में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के प्रथम बैच का तीन दिवसीय प्रशिक्षण 13 अप्रैल 2026 से प्रारम्भ हो गया है।

फील्ड ट्रेनर ने दिया विस्तृत प्रशिक्षण

प्रशिक्षण के पहले दिन फील्ड ट्रेनर द्वारा उक्त चार्ज अन्तर्गत समस्त प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को जनगणना प्रक्रिया की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जनगणना चार्ज लटोरी में शा.उ.मा.वि. भवन, लटोरी में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित फील्ड ट्रेनर्स एवं प्रगणकों से प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी प्राप्त की गई।

सॉफ्टवेयर हैण्डलिंग के दिए गए निर्देश

प्रशिक्षण में उपस्थित प्रगणकों को फील्ड ट्रेनिंग के साथ-साथ जनगणना सॉफ्टवेयर की हैण्ड होल्डिंग कराई गई। प्रशिक्षण सभा को उदाहरणों के माध्यम से अधिक रोचक एवं प्रभावी बनाया गया तथा प्रश्नोत्तर सत्र के जरिए कठिन बिन्दुओं को चिन्हाकित कर उनका समाधान किया गया। गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिभागियों के लिए भोजन-जलपान की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई।

ओवरलोड वाहनों से 4 गुना तक होगी शुल्क वसूली : टोल नाकों पर ही होगा वजन मापन, जानें नए नियमों की प्रमुख बातें

जयपुर, एजेंसी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) चौथा संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। यह संशोधन 15 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और इसका उद्देश्य ओवरलोडिंग पर नियंत्रण, शुल्क प्रणाली को सरल बनाना और सड़क सुरक्षा को मजबूत करना है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार अब अनुमेय सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) से अधिक वजन ले जाने वाले वाहनों पर संशोधित शुल्क संरचना लागू होगी। नए नियमों में ओवरलोडिंग के प्रतिशत के आधार पर शुल्क तय किया गया है।

दस फीसदी अतिरिक्त

भार पर माफ

नई व्यवस्था के तहत 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त भार पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं 10 से 40 प्रतिशत तक ओवरलोडिंग पर मूल दर का दोगुना शुल्क और 40 प्रतिशत से अधिक भार पर चार गुना शुल्क वसूला जाएगा। नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ओवर लोडिंग का निर्धारण केवल टोल प्लाजा पर स्थापित प्रमाणित वजन मापन उपकरणों के माध्यम से ही होगा। यदि किसी टोल प्लाजा पर वजन मापन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहां ओवरलोड शुल्क नहीं लगाया जा सकेगा।

ओवरलोडिंग शुल्क की वसूली फास्टैग से

डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ओवर लोडिंग शुल्क की वसूली अब केवल फास्टैग के माध्यम से ही होगी। साथ ही अधिक भार वाले वाहनों का पूरा विवरण दर्ज कर राष्ट्रीय वाहन रजिस्टर (वाहन) को भेजना अनिवार्य किया है। नियम कुछ पुरानी निजी निवेश परियोजनाओं पर तभी लागू होंगे, जब संबंधित रियायत ग्राही इसे अपनाने पर सहमत होंगे।

बीकानेर में अवैध जिप्सम खनन पर बड़ी कार्रवाई, चार मशीनें और दो वाहन जब्त

बीकानेर। जिला कलेक्टर निशान्त जैन द्वारा कार्यग्रहण के साथ ही खनिज विभाग को दिये गये निर्देशों के अनुसरण में माइंस एवं राजस्व विभाग बीकानेर की संयुक्त टीम ने जिप्सम के अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए को अवैध जिप्सम खनन चार मशीनरी व दो वाहन जब्त किए हैं। खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चक 24 ह्यद्वस्र में दबिश दी और मौके पर एक जेसीबी ,एक पोकलेन जेसीबी एवं 2 जिप्सम छानने की मशीनों द्वारा जिप्सम खनन करते हुए जब्त किया। खनि अभियंता, बीकानेर महेश प्रकाश पुरोहित द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मौके पर कुल 2875 टन खनिज जिप्सम का अवैध खनन किया जाना पाया गया। मौके से सभी चारों मशीनों को जब्त कर पुलिस थाना रणजीतपुरा को सूचित कर मौके पर बुलाकर सुपुर्दगी में दिया गया। खनिज अभियंता पुरोहित ने बताया कि इस जिप्सम खनन पर कुल 61,70,000/- रुपये की शास्ति राशि आरोपित की गई है। जिप्सम का ही अवैध परिवहन करते हुए दो वाहनों को जब्त कर रणजीत पुरा पुलिस को सुपुर्द किया गया है। यह कार्यवाही खनिकार्यदेशक अनिरूद्ध सिंह भाटी एवं बज्जू तहसीलदार मदन सिंह यादव के साथ भूअभिलेख निरीक्षक जगदीश एवं हल्का पटवारी रवि भान सिंह द्वारा की गई।

समाधान शिविरों की हुई समीक्षा, डीसी ने त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

राममेहर

हरियाणा: हांसी डीसी राहुल नरवाल की अध्यक्षता में जिला सचिवालय परिसर में समाधान प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त राहुल नरवाल शुक्रवार को चंडीगढ़ मुख्यालय से वीसी के माध्यम से जुड़े और हांसी के समाधान शिविरों की कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने उच्च अधिकारियों को भी वीसी के माध्यम से बताया कि समाधान शिविर में आई समस्याओं को गंभीरता से लेकर समाधान किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समाधान शिविरों में आने वाली सभी शिकायतों पर अविलंब कार्यवाही कर एक्शन टेकन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करें। एडीसी लक्षित सरीन ने इस दौरान एक-एक कर सभी विभागों से संबंधित लंबित शिकायतों की गहनता से समीक्षा की और सभी जन समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित आधार पर निवारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिकायतों के लंबित होने के कारणों की भी जानकारी प्राप्त की। एडीसी ने कोई जन समस्याओं के समाधान के लिए समय अवधि निर्धारित करते हुए इतने समय सीमा में कार्य पूर्ण करने की भी निर्देश दिए।

अधिकारियों की गाड़ियों के लिए बनेंगे शेड: एसडीएम राजेश खोथ ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से अधिकारियों की गाड़ियां खड़े करने के लिए बनाए जाने वाले शेड बनवाने के स्टेटस के बारे में जानकारी रखने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा अधिकारियों की गाड़ियां को खड़ा करने के लिए जिला सचिवालय परिसर में शेड बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। बहुत ही जल्द शेड निर्माण का कार्य शुरू करवाया जाएगा। प्रथम चरण में तीन गाड़ियों के लिए शेड बनेगा।

कांग्रेस के मजबूत प्रदर्शन का दावा करते हुए बोले पायलट- केरल, असम में कांग्रेस सरकार बनाएगी, भाजपा से दूरी बना रहे लोग

जयपुर। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के मजबूत प्रदर्शन का दावा करते हुए कहा कि केरल और असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पीसीसी में मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट ने कहा कि मेरा

आकलन यह है कि केरल में जबरदस्त वोटिंग हुई है और वोटिंग बदलाव का संकेत होता है, असम में भी बहुत अच्छी वोटिंग हुई है कोई कुछ भी कहे कांटे की टक्कर है वहां पर असम में भी, कांग्रेस पार्टी बहुमत में आएगी और केरल में हम निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे बदलाव हो रहा है भाजपा के शासन से पूरे देश में लोग ऊब चुके है। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर कहा कि सरकार को ना तो कोर्ट की चिंता है ना जनता की चिंता है कोई ना कोई अड़चन लगाकर चुनाव को टालना चाहते हैं। मैं अभी क्षेत्र का दौरा करके आया हूं नरेगा प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, प्रशासनिक अधिकारी जो काम कर रहे हैं वह जनता की भावना को लेकर चिंतित नहीं है। लोग परेशान दुखी हो रहे हैं लोग अपना रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, प्रधान, सरपंच ,प्रमुख, वार्ड मेंबर, महापौर, पार्षद यह सब महत्वपूर्ण होते हैं। भाजपा में हारने का डर है, क्योंकि चुनाव होंगे तो जनता उन्हें हरा सकती है। जनता का आक्रोश सामने आएगा इसलिए चुनाव नहीं कर रहे हैं। कानून में लिखा है कोर्ट के आदेश है फिर भी बहाने बाजी करके चुनाव टाल रहे हो तो सरकार बैकफुट पर है। राजधानी में यह हाल है तो बाकी जिलों में प्रदेश में क्या हाल होगा, सरकार को पहले तो लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए, यह सिर्फ भाषणों से नहीं होता आपको दबाव बनाना पड़ेगा

करोड़ों की सीसी रोड निर्माण में अनियमितताओं के आरोप, जांच की उठी मांग

भीलवाड़ा, एजेंसी। शहर के महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। मामले में करोड़ों रुपये के भुगतान और निविदा शर्तों की कथित अवहेलना को लेकर जांच की मांग उठ रही है। सूत्रों के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट योजना के तहत अस्पताल परिसर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सामने से लेकर सेवा सदन के छोटे गेट तक करीब 1.450 किलोमीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण प्रस्तावित था, जिसकी लागत लगभग 1.80 करोड़ रुपये बताई जा रही है।आरोप है कि निविदा शर्तों में सड़क निर्माण के लिए स्लिप फॉर्म पेवर मशीन का उपयोग अनिवार्य किया गया था, जो आमतौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हाईवे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होती है। इस शर्त के कारण कई ठेकेदारों ने निविदा प्रक्रिया से दूरी बना ली, जिससे प्रतिस्पर्धा सीमित हो गई।

सूत्रों का यह भी दावा है कि संबंधित ठेकेदार ने मशीन का उपयोग किए बिना ही कथित रूप से बाहरी कारीगरों से सड़क का निर्माण करवा दिया, जिसे विभागीय अधिकारियों ने स्वीकृति देते हुए भुगतान भी जारी कर दिया। विभाग के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस प्रकार की मशीनें राज्य में बहुत कम ठेकेदारों के पास उपलब्ध हैं, और इनके संचालन व परिवहन में भारी खर्च आता है। ऐसे में आरोप है कि निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य नहीं होने से लागत और गुणवत्ता दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

भारत अफ्रीका की ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में निभा सकता है अहम भूमिका

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। भारत अफ्रीका को अपनी रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने में मदद करने में अहम भूमिका निभा सकता है। भारत ने पिछले दस सालों में 130 गीगावाट से ज्यादा सोलर और विंड कैपेसिटी सफलतापूर्वक जोड़ी है। अब रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड बिजली कैपेसिटी का लगभग आधा हिस्सा है।

इंडिया नैरेटिव की आर्टिकल के अनुसार, ह्लपूरे अफ्रीका में एनर्जी ट्रांजिशन कोई दूर का पॉलिसी टारगेट नहीं है। यह सूरज की रोशनी, हवा और मिनरल की दौलत को रेगुलर बिजली वाले हॉस्पिटल, सूरज डूबने के बाद सिंचाई करने वाले खेत और महंगे डीजल जनरेटर के बजाय ज्यादा भरोसेमंद चीजों से जुड़ने वाली फैक्ट्रियों में बदलने की एक प्रैक्टिकल कोशिश है। इसमें बताया गया है कि अफ्रीका में 600 मिलियन लोग अभी भी बिजली के बिना हैं, हालांकि एक्सेस रेट बढ़ रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। इसमें इस ट्रांजिशन को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी और संस्थागत अनुभव देने में भारत के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखता है। जोरी अमोंडी ने अपने लेख में लिखा है कि भारत में सौर ऊर्जा का विस्तार प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया, स्पष्ट नीतिगत संकेतों और छोटे शहरों के ग्रिड के साथ-साथ गांवों तक पहुंचने वाले विकेंद्रीकृत सोलर सिस्टम पर ध्यान देने की वजह से संभव हुआ है।

उन्होंने कहा कि अफ्रीकी देशों के लिए इससे कई सीखें ली जा सकती हैं, जैसे पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया, पहले से तय टैरिफ और मजबूत घरेलू इंजीनियरिंग आधार विकसित करना। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इन उपायों को अपनाते समय प्रत्येक देश को अपने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नियामक ढांचे में जरूरी बदलाव करने होंगे।

अफ्रीकी महाद्वीप को लगभग किसी भी दूसरे इलाके से ज्यादा सोलर रेडिएशन मिलता है और 2020 और 2025 के बीच, अफ्रीकी सरकारों और प्राइवेट निवेशकों ने पहले ही लगभग 25 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी देने का वादा किया है और प्राइवेट सेक्टर डील्स के जरिए 11 गीगावाट और हासिल किए हैं। अब सिर्फ सोलर ही नई कैपेसिटी का ज्यादातर हिस्सा है।

इसके अलावा, आर्टिकल में बताया गया है कि कई अफ्रीकी देशों में, नई सोलर पावर नए गैस से चलने वाले प्लांट बनाने से सस्ती है, खासकर जब ट्रांसमिशन और फ्यूल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को भी ध्यान में रखा जाता है।

इसमें यह भी बताया गया कि अफ्रीका अपने जरूरी मिनरल्स के जरिए ग्लोबल क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा है। इस कॉन्टिनेंट में दुनिया के कोबाल्ट, कॉपर, मैंगनीज, प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स का एक बड़ा हिस्सा और लिथियम का बढ़ता हुआ हिस्सा है, ये ऐसे मटेरियल हैं, जो बैटरी, इलेक्ट्रोलाइजर और विंड टर्बाइन को मजबूत बनाते हैं, जिससे अफ्रीका ग्लोबल इंडस्ट्रियल इकॉनोमी में हिस्सा ले पाएगा।

आर्टिकल में बताया गया है कि इंडियन यूटिलिटीज ने पहले ही ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, एनर्जी स्टोरेज और वेरिएबल रिन्यूएबल्स के इंटीग्रेशन पर अफ्रीकी काउंटरपार्ट्स के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स पर अफ्रीका50 और दूसरे अफ्रीकी इंस्टीट्यूशन्स के साथ पार्टनरशिप की है, जो देशों में सोलर और विंड को एक साथ लाने और अलग-थलग फॉसिल फ्यूल प्लांट्स पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकते हैं।

आर्टिकल में कहा गया, ह्लभारत पेशेंट फाइनेंसिंग बढ़ाकर, ग्रिड इंटीग्रेशन और सोलर पंप स्कीम पर मुश्किल से सीखे गए सबक शेयर करके, और जरूरी मिनरल्स की वैल्यू एडिशन के लिए अफ्रीका के नियमों का समर्थन करके मदद कर सकता है।

ट्रंप ने दिया मौका भारत ने लपक लिया

7 साल में पहली बार हुआ ऐसा, ईरान भी खुश

नई दिल्ली, एजेंसी। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच भारत को ईरान से लगभग 40 लाख बैरल कच्चा तेल (क्रूड) मिला है। करीब सात सालों में यह पहली बार है जब भारत ने ईरान से कच्चा तेल खरीदा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरानी तेल खरीद के लिए एक डेडलाइन तय की है। भारत इस समयसीमा से पहले ही सप्लाई सुरक्षित करना चाहता है। यह डेडलाइन

इस वीकेंड पर खत्म हो रही है। भारत आयातित ऊर्जा पर बहुत अधिक निर्भर है। यह चीज उसे कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाती है। भारत ने फरवरी के अंत से ग्लोबल ऑयल फ्लो में आई रुकावटों का असर महसूस किया है। अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद ऐसा हुआ है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में मामले से परिचित सूत्रों और इंटेलिजेंस फर्मों केप्लर और वोर्टेक्सा के जहाज-ट्रैकिंग डेटा का हवाला दिया गया है। इसमें बताया गया है कि 'जया' नाम का एक बड़ा क्रूड कैरियर इस समय भारत के पूर्वी तट पर स्थित पारादीप में अपना माल उतार रहा है। यह ईरानी तेल से पूरी तरह भरा हुआ है। एक अन्य टैंकर 'फेलिसिटी' पश्चिमी तट पर स्थित सिक्का में इसी तरह का काम कर रहा है। ब्लूमबर्ग न्यूज के मुताबिक, ये दोनों जहाजों के शुक्रवार तक भारतीय बंदरगाहों से रवाना होने की उम्मीद है। इन पर अमेरिका के प्रतिबंध लगे हुए हैं। पारादीप में कच्चे तेल की खेप को संभालने का काम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन करता है। वहीं, सिक्का का इस्तेमाल रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की ओर से किया जाता है। ये इस क्षेत्र में एक 'सिंगल-पॉइंट मूरिंग' फैसिलिटी को ऑपरेट करते हैं।

ईरानी तेल के साथ पेमेंट की मुश्किल

पिछले साल तक भारत समंदर के रास्ते आने वाले रूसी कच्चे तेल का प्रमुख आयातक था। उसने इन खरीदों में तेजी से बढ़ोतरी की थी। हालांकि, लगातार जारी वित्तीय प्रतिबंधों के कारण रिफाइनरियों को ईरानी खेप की खरीद और उसके पेमेंट में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। भारत ने संकेत दिया था कि सप्लाई में जारी कमी से निपटने के लिए वह अन्य स्रोतों के साथ ईरान से भी कच्चा तेल खरीदेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि टैंकर 'जया' और 'फेलिसिटी' की ओर से लाई गई खेप का आगमन दिखाता है कि इन आयातों को सुगम बनाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं।

भारत पर बढ़ता दबाव

पेट्रोल-डीजल के दाम न बढ़ाकर रोक रखा है सैलाब, हर दिन 1,600 करोड़ का नुकसान

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में पेट्रोल पंप पर ईंधन की कीमतें अभी स्थिर दिख रही हैं। लेकिन, पर्दे के पीछे कहानी बिगड़ी हुई है। तेल कंपनियां इन कीमतों को ऐसे ही बनाए रखने के लिए भारी नुकसान उठा रही हैं। इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक, सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां (ओएमसी) मिलकर हर दिन करीब 1,600 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रही हैं। इन कंपनियों में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड शामिल हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है जब 28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से भू-राजनीतिक तनाव बढ़ा है। इसके कारण कच्चे तेल की ग्लोबल कीमतें बढ़ गई हैं। वहीं, भारत में खुदरा ईंधन की कीमतें काफी हद तक जस की तस रही हैं। 135-165 डॉलर प्रति बैरल की मौजूदा (स्पॉट) पेट्रोल-डीजल कीमतों पर हमारा अनुमान है कि भारत की तेल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर 18 रुपये और 35 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। अगर घरेलू ईंधन की कीमतें कच्चे तेल के वैश्विक रुझानों को पूरी तरह से दर्शातीं तो मौजूदा अनुमानों के अनुसार, पेट्रोल लगभग 113 रुपये प्रति लीटर और डीजल 123 रुपये प्रति लीटर बिक रहा होता। इसके बजाय ओएमसी इस अंतर को खुद

वहन कर रही हैं। पेट्रोल-डीजल की कीमतों को नियंत्रण-मुक्त करने के बावजूद इन कंपनियों ने अप्रैल 2022 के बाद से खुदरा दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। सूत्रों के हवाले से पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, इससे नुकसान बढ़कर पेट्रोल पर लगभग 18 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 35 रुपये प्रति लीटर हो गया है। मैक्वेरी ग्रुप की एक रिपोर्ट ने इस दबाव की गंभीरता का जिक्र किया। रिपोर्ट में कहा गया, '135-165 डॉलर प्रति बैरल की मौजूदा (स्पॉट) पेट्रोल-डीजल कीमतों पर हमारा अनुमान है कि भारत की तेल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर 18 रुपये और 35 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है।' रिपोर्ट में आगे कहा गया, 'कच्चे तेल की कीमतों में हर 10 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी से मार्केटिंग में होने वाला नुकसान लगभग 6 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाता है।' एक समय जब कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी थीं तो दैनिक नुकसान 2,400 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। इसके बाद यह कम होकर मौजूदा 1,600 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। सरकार ने इस दबाव को कुछ हद तक कम करने के लिए हस्तक्षेप किया है। लेकिन, इसकी भी एक कीमत चुकानी पड़ी है। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती से ओएमसी पर पड़ने वाले बोझ को कम करने में मदद मिली। हालांकि, कंपनियों ने इस लाभ को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के बजाय अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए इसे खुद ही रखा।

रुपया 10 पैसे की बढ़त के साथ 93.23 प्रति डॉलर पर

मुंबई, (वेब वार्ता)। पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम की उम्मीदों के बीच वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते रुपया बृहस्पतिवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत होकर 93.23 (अस्थाई) पर रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि आयातकों की ओर से डॉलर की मांग बढ़ने और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी ने स्थानीय मुद्रा की बढ़त को सीमित कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि कच्चे तेल की कीमतें 95 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहने से घरेलू मुद्रा में तेजी आई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 93.29 पर खुला और दिन के कारोबार में डॉलर के मुकाबले 93.16 के ऊपरी और 93.35 के निचले स्तर तक गया। कारोबार के अंत में यह 93.23 (अस्थाई) पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से 10 पैसे की बढ़त है। रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दो पैसे बढ़कर 93.33 पर बंद हुआ था। एलकेपी सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष शोध विश्लेषक (जिंस एवं मुद्रा) जतिन त्रिवेदी ने कहा कि रुपये की बढ़त मुख्य रूप से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीदों से प्रेरित है। इस वजह से पिछले 48 घंटों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है और इससे भारत के आयात बिल पर दबाव कम हुआ है। त्रिवेदी ने कहा, ह्यहालांकि, यह सुधार नाजुक बना हुआ है, क्योंकि बाजार की भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर करीब से नजर है और कच्चे तेल की कीमतों में किसी भी तरह की तेजी का असर रुपये पर तुरंत पड़ सकता है।

पहले की तरह धड़ाधड़ गैस सिलेंडर मिलने में लगेंगे कई साल, सप्लाई चेन चरमराई

नई दिल्ली, एजेंसी। दुनियाभर में एलपीजी सप्लाई चेन में रुकावट आई है। इसे ठीक होने में तीन से चार साल लग सकते हैं। अभी यह साफ नहीं है कि प्रोडक्शन कुछ समय के लिए रुका है या उसे हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से 'मनी कंट्रोल' ने यह जानकारी दी है। इसका सीधा मतलब है कि पहले की तरह धड़ाधड़ एलपीजी गैस सिलेंडर मिलने में अभी कई साल का इंतजार करना पड़ सकता है। यह भारत के लिए अच्छा नहीं है। अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर 'मनी कंट्रोल' से कहा, 'प्रभावित सप्लायरों से मिली जानकारी के आधार पर सप्लाई को फिर से शुरू करने में कम से कम तीन साल और शायद उससे भी ज्यादा समय लग सकता है।' उन्होंने भारत के बढ़ते आयात जोखिमों और लागत के दबाव की ओर भी इशारा किया। युद्ध से पहले और बाद की स्थिति

ईरान युद्ध शुरू होने से पहले इस सप्लाई का लगभग 90 फीसदी हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते ही आता था। 24 मार्च तक खाड़ी देशों से होने वाले आयात का हिस्सा घटकर 55 फीसदी रह गया था। यह इस बात का संकेत है कि सप्लाई में रुकावट आई है। साथ ही भारत ने सप्लाई के नए स्रोत भी खोजे हैं। रुबिक्स डेटा साइंसेज और वयाना ट्रेडएक्सचेंज की अप्रैल में आई एक रिपोर्ट के

अनुसार, सप्लाई के रास्ते बदलने और नए स्रोत खोजने के बाद भी सप्लाई में रुकावट का असर 40-50 फीसदी तक बना रह सकता है। रुबिक्स डेटा साइंसेज रिस्क मैनेजमेंट और एनालिटिक्स कंपनी है। वहीं, वयाना ट्रेडएक्सचेंज सप्लाई-चेन फाइनेंस और ट्रेड डेटा का एक प्लेटफॉर्म है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की सालाना एलपीजी मांग लगभग 3.3 करोड़ टन है। मार्च के मध्य तक भारत के पास केवल 15 दिनों की खपत के बराबर ही एलपीजी का भंडार मौजूद था।

ऐसे में सप्लाई के स्रोतों में बदलाव होने से कम समय के लिए सप्लाई में रुकावट का जोखिम बढ़ जाता है। कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का भी सामना करना पड़ सकता है। मार्च के मध्य से घरेलू 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें 60 रुपये बढ़ गई हैं। इसी दौरान कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में 115 रुपये का इजाफा हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान ने मिलकर वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की 92 फीसदी एलपीजी की सप्लाई की।

दिग्गज कंपनियों के शेयरों में मुनाफावसूली, प्रमुख सूचकांक टूटे

मुंबई। घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को शुरूआती तेजी के बाद दिग्गज कंपनियों में ऊंचे भाव पर मुनाफावसूली देखी गई और प्रमुख सूचकांक गिरावट में बंद हुए। सुबह 566 अंक चढ़कर खुलने वाला बीएसई का सेंसेक्स 122.56 अंक (0.16 प्रतिशत) गिरकर 77,988.68 अंक पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 34.55 अंक यानी 0.14 प्रतिशत नीचे 24,196.75 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज एक हजार अंक से अधिक का उतार-चढ़ाव रहा। यह ऊपर 78,730.32 अंक और नीचे 77,674.93 अंक तक गया।

भारत के बड़े शहरों में होटल के कमरे खाली

युद्ध ने बिगाड़ा काम

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की वजह से भारत के कई सेक्टरों पर सीधा असर पड़ा है। होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे जीसीसी शहरों में होटलों की ऑक्यूपेंसी गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। कारण है कि भारत आने वाले ज्यादातर विदेशी यात्री दुबई, अबू धाबी और दोहा जैसे एविएशन हब से होकर आते हैं। जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ऐसे केंद्र होते हैं जिन्हें बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां (एमएनसी) अपने देश से बाहर दूसरे देशों में स्थापित करती हैं। इनमें हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली-एनसीआर जैसे शहर शामिल हैं। 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल ने ईरान पर हमले किए। ईरान ने भी पलटवार किया। उसने कई खाड़ी देशों में अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया। इससे यह संकट पूरे क्षेत्र में फैल गया। इसने हवाई यातायात को भी प्रभावित किया। शैले होटल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्वेतांक सिंह ने बिजनेस टुडे को बताया, 'पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से होटल

बिजनेस पर असर पड़ा है। विदेशी पर्यटकों के आने में कमी आई है। इसका असर बड़े शहरों के बड़े होटलों की ऑक्यूपेंसी पर पड़ा है।' सिंह ने कहा, 'मिडिल ईस्ट के रास्ते यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को देखूं तो 40 प्रतिशत बिजनेस विदेशी पर्यटकों से आता है। बड़े शहरों के बड़े होटलों का हिस्सा हमारे पोर्टफोलियो में लगभग 60 प्रतिशत है। साफ तौर पर इसका असर दिख रहा है।' उन्होंने आगे कहा, 'ये यात्री होटल के अंदर ज्यादा खर्च करते हैं। ज्यादा समय तक रुकते हैं। वे अपने साथ एक पूरा ग्रुप लेकर चलते हैं।' सिंह ने बताया, 'हालांकि, लक्जरी रिजॉर्ट का बिजनेस अच्छा चल रहा है। लेकिन, कुल मिलाकर हमें जितना फायदा हुआ है, उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। मार्च में ऑक्यूपेंसी 10 प्रतिशत तक गिर गई है। जीसीसी से जुड़ी यात्राओं की वजह से बेंगलुरु और हैदराबाद पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा है।' हालांकि, प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी अनुभवों की बुनियादी मांग अभी भी बनी हुई है। इस पर भू-राजनीतिक हालात की वजह से कुछ हद तक असर पड़ा है। पिट्टी ने आगे कहा, 'मार्च के महीने में हमने बड़े शहरों के लक्जरी होटलों की बुकिंग में अचानक आई भारी गिरावट के बजाय कुछ हद तक बदलाव या रीकैलिब्रेशन देखा है। हालांकि, पश्चिम एशिया में हो रहे भू-राजनीतिक घटनाक्रमों की वजह से अंतरराष्ट्रीय यात्रा के कुछ खास हिस्सों पर असर पड़ा है। लेकिन, घरेलू यात्रियों और बिजनेस ट्रैवल्स के सहारे कुल मांग काफी हद तक स्थिर बनी हुई है।' हवाई किराए में हुई भारी बढ़ोतरी का भी मांग पर असर पड़ रहा है। पिट्टी ने कहा, 'फ्यूल सरचार्ज और ऑपरेशनल खर्चों में बढ़ोतरी की वजह से हवाई किराए में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। घरेलू रूट्स पर किराए में लगभग 5-10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

पीएफ खाते से विड्रॉल टीडीएस बचाने के लिए अब नहीं चलेंगे पुराने फॉर्म, बदल गया है नियम

नई दिल्ली, एजेंसी। पीएफ खाताधारकों के लिए टैक्स से जुड़े नियम बदल गए हैं। अब पीएफ से पैसा निकालते समय टीडीएस बचाने के लिए पुराने फॉर्म नहीं चलेंगे। इनकी जगह फॉर्म 121 शुरू किया है। नियम 1 अप्रैल से लागू है। फॉर्म भरने वाले को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी साल भर की टैक्स लायबिलिटी जीरो है। कंपनियां, फर्में और एनआरआई इस फॉर्म को भरने के पात्र नहीं हैं। 13 अप्रैल को जारी अपने सर्कुलर में ईपीएफओ ने बताया कि पहले 60 साल से कम उम्र के लोग फॉर्म 15ज भरते थे और सीनियर सिटीजन फॉर्म 15॥ का इस्तेमाल करते थे। अब इन दोनों की जगह केवल फॉर्म 121 इस्तेमाल होगा। यह फॉर्म केवल उन लोगों के लिए है जिनकी पूरे साल की कुल अनुमानित कमाई पर टैक्स की देनदारी शून्य है। यानी अगर आपकी सालाना कमाई टैक्स छूट की सीमा से कम है, तो आप इस फॉर्म को भरकर अपनी

इनकम बिना ञ्झष्ठस् कटे हासिल कर सकते हैं। ईपीएफओ ने साफ किया है कि यह फॉर्म सबके लिए जरूरी नहीं है। यह केवल उन लोगों के लिए है जो टीडीएस कटने से बचना चाहते हैं। ईपीएफओ ने कहा है कि 1 अप्रैल के बाद अगर किसी ने पुराने फॉर्म के साथ क्लेम फाइल कर दिया है, तो उसे रिजेक्ट करके वापस नहीं भेजा जाएगा। हालांकि, कर्मचारी से फॉर्म 121 लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए पीएफ एक अनिवार्य सरकारी बचत योजना है। इसमें कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है जबकि कंपनी भी इतना ही योगदान देती है। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है।

100 करोड़ की डील ने बदली किस्मत! 16

प्रतिशत उछला रियल एस्टेट स्टॉक

रियल एस्टेट स्टॉक में अचानक तेजी!

नई दिल्ली, एजेंसी। रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी सूरज एस्टेट डेवलपर्स के शेयरों में हाल ही में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जिसने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कंपनी के शेयर एक ही दिन में करीब 16 प्रतिशत तक उछल गए, जिसकी सबसे बड़ी वजह मुंबई के दादर (वेस्ट) इलाके में एक नई लैंड डील है। कंपनी ने इस जमीन को करीब 18 करोड़ की कुल लागत (कैश + एरिया) में हासिल किया है, जबकि इस प्रोजेक्ट से संभावित ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू करीब 100 करोड़ बताई जा रही है। आसान भाषा में समझें तो कंपनी इस जमीन पर नया प्रोजेक्ट बनाकर लगभग 100 करोड़ का बिजनेस करने की उम्मीद कर रही है, जो निवेशकों के लिए पॉजिटिव संकेत माना जाता है। यह जमीन मुंबई के दादर जैसे प्राइम लोकेशन में है, जहां रियल एस्टेट की डिमांड हमेशा बनी रहती है। कंपनी इस प्लॉट पर री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करेगी, जिसमें करीब 0.18 लाख स्क्वॉयर फीट का सेलएबल एरिया तैयार किया जाएगा, यानी कंपनी पुराने स्ट्रक्चर को हटाकर नया प्रोजेक्ट बनाएगी और उसे बेचकर मुनाफा कमाएगी। यही वजह है कि बाजार ने इस खबर को पॉजिटिव तरीके से लिया और शेयर में तेजी आ गई।

अगर शेयर के पिछले प्रदर्शन पर नजर डालें तो यह स्टॉक अपने 52 हफ्ते के हाई 398 से अभी भी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हाल की तेजी यह दिखाती है कि निवेशकों का भरोसा फिर से लौट रहा है। वहीं, यह अपने 52 हफ्ते के लो 168.80 से काफी ऊपर आ चुका है, जो संकेत देता है कि इसमें रिकवरी का ट्रेंड चल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 1,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है, यानी यह एक स्मॉल-कैप कंपनी है, जहां ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन जोखिम भी उतना ही रहता है।

डायबिटीज के आंकड़ों ने दिया आइडिया, नौकरी को मारी लात, अब सालाना 2 करोड़ की कमाई

नई दिल्ली, एजेंसी। हर्षवर्धन एस बेंगलुरु के रहने वाले हैं। नौकरी छोड़कर उन्होंने सफल ब्रांड खड़ा कर दिया है। भारत में डायबिटीज के डरावने आंकड़ों और खान-पान की गलत आदतों ने उन्हें इसका आइडिया दिया। उनके ब्रांड का नाम लिल गुडनेस है। इसकी नींव उन्होंने अपने दोस्त दमनबीर सिंह के साथ डाली। यह ब्रांड हेल्दी स्नैक्स और पोषण से भरपूर फूड आइटम बेचता है। अब वे इससे सालाना 2 करोड़ की कमाई कर रहे हैं। आइए, यहां हर्षवर्धन एस की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं। हर्षवर्धन एस पहले टाटा हेल्थ में नौकरी करते थे। जॉब के दौरान तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर किए गए एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम ने उनकी आंखें खोल दीं। करीब 13 लाख लोगों की जांच में 2,600 लोग गंभीर डायबिटीज से पीड़ित पाए गए। बड़ी बात यह कि उन्हें अपनी बीमारी का अंदाजा तक नहीं था। इस अनुभव ने हर्षवर्धन को झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि समाज में मेटाबॉलिक विकारों को रोकने के लिए न्यूट्रीशन के स्तर पर बड़े बदलाव की जरूरत है। इसी सामाजिक सरोकार को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जमी-जमाई नौकरी छोड़ने का साहसी फैसला लिया।

इस बात पर किया फोकस

हर्षवर्धन ने हेल्थ के साथ टेस्ट के कॉम्बिनेशन पर फोकस किया। 'प्रीबायोटिक डार्क चॉकलेट' पेश की। इसकी कीमत सिर्फ 20 रुपये रखी गई। मकसद था कि हर तबके तक यह पहुंचे। इसके अलावा उनके उत्पादों में क्विनोआ और टेफ जैसे सुपर ग्रेस से बने स्नैक्स और 40 प्रतिशत कम चीनी वाले मिल्क शेक शामिल हैं। उन्होंने पैकेजिंग को भी खास बनाया। इसमें एवेंजर्स और डिज्नी के किरदारों के जरिए बच्चों को गट-हेल्थ के प्रति जागरूक किया जाता है। हर्षवर्धन ने 19 फुल-टाइम कर्मचारियों और करीब 70 वंचित वर्ग की महिलाओं को रोजगार देकर अपनी परोपकारी सोच को भी कायम रखा है। आने वाले समय में वह अपनी पहुंच 10,000 स्टोर्स तक बढ़ाने और स्कूल कैंटीनों में अपनी जगह बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं।

2020 में रखी ब्रांड की नींव

हर्षवर्धन के इस सफर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसी साल वह एक बेटी के पिता बने। एक पिता के तौर पर वह चाहते थे कि उनकी बेटी को बचपन से ही बाजार में उपलब्ध मिलावटी और बहुत ज्यादा शुगर वाले स्नैक्स के बजाय हेल्दी ऑप्शन मिलें। उन्होंने महसूस किया कि बाजार में मिलने वाली सस्ती चॉकलेट्स में सिर्फ शुगर और वेजिटेबल फैट होता है। वहीं, हेल्दी ऑप्शन आम आदमी की जेब से बाहर हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने 2020 में अपने साथी दमनबीर सिंह के साथ मिलकर लिल गुडनेस की शुरुआत की। अपनी शुरुआत होने से सिर्फ तीन सालों में ब्रांड देश के करीब 4,000 किराना स्टोर तक पहुंच गया। अब तक 16 लाख से अधिक ग्राहकों ने इसकी सेवाएं ली हैं। इसका टर्नओवर सालाना 2 करोड़ हो गया है।

संक्षिप्त

हम मैच में हमेशा आगे रहेः विराट

बेंगलुरु, एजेंसी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हुए सिर्फ 15.1 ओवर में 149 रन का टारगेट चेज करते हुए पांच विकेट से जीत हासिल की। आरसीबी की बॉलिंग यूनिट ने शानदार कोशिश से नींव रखी, जिसमें भुवनेश्वर कुमार ने फ्रेंचाइजी के लिए अपने बेस्ट फिगर (3/27) के साथ आगे बढ़कर लीड किया, जबकि रसिख सलाम ने 4/24 के करियर के बेस्ट आईपीएल फिगर के साथ शानदार परफॉर्मेंस दी। जोश हेजलवुड ने आरसीबी के लिए सीजन का सबसे किफायती स्पेल (1/20) फेंककर इस कोशिश को पूरा किया, क्योंकि अटैक ने प्लान को सटीकता से पूरा किया। यह मैच क्रुणाल पांड्या (2/38) के लिए भी एक अहम मील का पत्थर साबित हुआ, जिन्होंने आईपीएल में 100 विकेट पूरे किए, जिससे आरसीबी की ऑल-राउंड गहराई और मजबूत हुई। जीत के बाद कोहली ने कहा, "बॉलिंग ग्रुप ने इसे बहुत अच्छे से सेट किया।

आर वैशाली ने जीता फिडे विमेंस कैंडिडेट्स का खिताब

साइप्रस/नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने फिडे विमेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया। वह यह खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। केन्द्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इस उपलब्धि पर वैशाली को बधाई दी। बुधवार को 14 राउंड के इस मुकाबले में आखिरी राउंड में कतेरीना लाग्नो को हराकर वैशाली ने खिताब अपने नाम किया। इस खिताबी जीत के साथ ही उन्होंने इस साल के आखिर में होने वाली विश्व चैंपियनशिप का टिकट मिल गया है, जहां उनका सामना चीन की जू वेनजुन से होगा। केन्द्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आर वैशाली को बधाई दी है।

आईजीपीएल गोल्फः ओलंपियन माने, सोनी और शाह संयुक्त बढ़त पर

जोहानिसबर्ग, एजेंसी। ओलंपियन उदयन माने, मिलिंद सोनी और मानव शाह ने यहां आईजीपीएल इनविटेशनल साउथ अफ्रीका गोल्फ टूर्नामेंट के पहले दौर में समान सात अंडर 65 का स्कोर बनाकर संयुक्त बढ़त हासिल की।

यह तीनों खिलाड़ी पिछले साल के आईजीपीएल रैंकिंग विजेता पुखराज सिंह गिल (66) से एक शॉट आगे हैं।

गगनजीत भुल्लर, करनदीप कोचर और सार्थक छिब्बर पांच अंडर 67 के स्कोर के साथ संयुक्त पांचवें स्थान पर हैं।

पहले दिन के बाद महिला खिलाड़ियों में विधात्री उर्स और वाणी कपूर सबसे आगे हैं। इन दोनों ने पार 72 का स्कोर बनाया। दोनों ने दो-दो बर्डी और दो-दो बोगी लगाईं।

संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 2 फ्रेंडली मैच खेलेगी भारत की अंडर-17 मेंस टीम

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय अंडर-17 मेंस टीम 17 और 21 अप्रैल को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 2 दोस्ताना मैच खेलेगी। यह मुकाबले थाईलैंड के समुत प्राकन स्थित विंडमिल फुटबॉल क्लब में आयोजित होंगे। एएफसी अंडर-17 एशियन कप सऊदी अरब 2026 के लिए भारत और यूएई की तैयारियों का हिस्सा है। दोस्ताना मैच बंद दरवाजों के पीछे खेले जाएंगे। दोनों मैच बैंकॉक के पास समुत प्राकन में विंडमिल फुटबॉल क्लब में भारतीय समय के अनुसार शाम 4.30 बजे से शुरू होंगे। 24 सदस्यीय ब्लू कोल्ट्स का दस्ता बुधवार 15 अप्रैल को थाईलैंड पहुंच गया है। पिछले महीने, बिबियानो फर्नांडीस की टीम ने थाईलैंड के लोपबुरी में थाईलैंड (2-2), इंडोनेशिया (3-0 से जीत) और कोरिया गणराज्य (1-2 हार) के खिलाफ तीन मैत्री मैच खेले थे।

इस सीजन जीत का खाता खोलने को बेताब केकेआर

केकेआर ने अब तक 5 मैच खेले हैं, 4 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा

- **गुजरात टाइटंस को बल्लेबाजी में कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन से खासा उम्मीदें होंगी**

अहमदाबाद, एजेंसी।

गुजरात टाइटंस (जीटी) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बीच शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का 25वां मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें केकेआर का लक्ष्य जीत का खाता खोलना होगा। यह मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा।

आईपीएल 2026 में केकेआर ने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें 4 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में, इस सीजन नाइट राइडर्स का एकमात्र अंक ईडन गार्डन्स में पंजाब किंग्स के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हुए मैच से आया था।

केकेआर को बल्लेबाजी में कप्तान अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी से उम्मीदें होंगी। गेंदबाजी में वैभव अरोड़ा और सुनील नरेन कोलकाता नाइट राइडर्स की आस होंगे। जीटी आईपीएल के अपने अगले मैच के लिए घरेलू मैदान लौट रही है। यह टीम 4 में से 2 मुकाबले गंवाकर प्वाइंट्स टेबल में छठे स्थान पर मौजूद है। पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शुरुआती 2 मुकाबले गंवाने के बाद जीटी ने दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के विरुद्ध मुकाबले अपने नाम किए थे।

इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस को बल्लेबाजी में कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन से खासा उम्मीदें होंगी। वहीं, गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान इस टीम को मजबूती देते हैं।

गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक कुल 5 मैच खेले गए हैं, जिसमें जीटी का पलड़ा भारी रहा है। टाइटंस ने 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि एक मैच केकेआर के पक्ष में रहा। वहीं, एक मुकाबला बेनतीजा रहा।

गुजरात टाइटंसः शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, इशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, अरशद खान, अनुज रावत, कुलवंत खेजरोलिया, गुरनूर बरार, एम शाहरुख खान।

कोलकाता नाइट राइडर्सः अजिंक्य रहाणे (कप्तान), मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती, कैमरून ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, कार्तिक त्यागी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, तेजस्वी दहिया, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, आकाश दीप, प्रशांत सोलंकी, दक्ष कामरा।

चोटिल खलील अहमद आईपीएल 2026 से हुए बाहर

चेन्नई, एजेंसी।

दाई जांघ में चोट के कारण चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के शेष मैचों से बाहर हो गये हैं।

सीएसके की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है, "इस चोट को ठीक होने में 12 हफ्तो से अधिक का समय लगेगा।"

खलील की चोट से सीएसके की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि टीम पहले से ही एमएस धोनी और नाथन एलिस के बिना खेल रही है। धोनी अभी पिंडली की चोट से उबर रहे हैं और उनकी रिकवरी दो सप्ताह से अधिक खिंच चुकी है। हालांकि धोनी टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने पूरी तरह से अभ्यास शुरू नहीं किया है। नाथन एलिस पूरे सीजन से बाहर हैं, जबकि उनके रिप्लेसमेंट स्पेंसर जॉनसन भी चोट से उबर रहे हैं और अभी तक टीम से नहीं जुड़े हैं।

महाराष्ट्र के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी और रामकृष्ण घोष खलील की जगह लेने के विकल्प हैं। जहां बाएं हाथ के मुकेश चौधरी सीधे तौर पर उनकी जगह ले सकते हैं, वहीं घोष दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं जो बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं।

घोष ने 2025-26 घरेलू सीजन में महाराष्ट्र के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने जयपुर में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 42 रन देकर सात विकेट लिए थे।

यूएस ओपन पिकलबॉलः भारत के अर्जुन-आदित्य ने स्वर्ण और ठक्कर-शेठ ने रजत पदक जीता

मुंबई, एजेंसी।

भारतीय जोड़ी अर्जुन सिंह और आदित्य सिंह ने यूएस ओपन पिकलबॉल चैंपियनशिप 2026 में पुरुष डबल्स 5.0 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में जे मेओड और डब्ल्यू लिन को 9-11, 11-2, 11-7 से हराया। अर्जुन और आदित्य की जोड़ी ने पहला गेम हारने के बाद जोरदार वापसी करते हुए खिताब जीता।

एक और शानदार मैच में पंथ ठक्कर और अथर्व शेठ ने पुरुष डबल्स 4.5 श्रेणी में रजत पदक जीता। यह जोड़ी कायन एपेल और माइकल वैन ड्यूसेन के खिलाफ एक करीबी मुकाबले में हार गई। स्कोरलाइन 8-11, 9-11 रहा। फ्लोरिडा के नेपल्स में हो रही यह चैंपियनशिप, इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन (आईपीए) से जुड़े होने के तहत भारत की पहली भागीदारी है।

चैंपियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के बाद अर्जुन और आदित्य ने कहा, "यूएस ओपन में एक और स्वर्ण जीतना बहुत फायदेमंद है और इसे एक बार फिर साथ में करना इसे और भी खास बनाता है। हम अपने परिवार और अपने आस-पास के सभी लोगों के समर्थन से इन नतीजों को दोहराने के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे। यह महाराष्ट्र पिकलबॉल एसोसिएशन और इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन के बिना मुमकिन नहीं होता।

इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्यवीर सिंह भुल्लर ने कहा, "यूएस ओपन में हर एक दिन भारतीय पिकलबॉल के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और वैश्विक मंच पर अपनी जगह पक्की करने का एक और दिन होता है और टीम इस चुनौती के लिए तैयार है। यह पिकलबॉल के मक्का में भारत का चौथा स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर छठा पदक है। इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन को इस बात पर बहुत गर्व है कि खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यह हमें और बेहतर करने के लिए और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है।

यह जीत यूएस ओपन पिकलबॉल चैंपियनशिप में अर्जुन का तीसरा स्वर्ण पदक है और उनके भाई आदित्य के साथ उनका दूसरा पदक है। यूएस ओपन 2026 में भारत के पदकों की संख्या अभी छह है, जिसमें चार स्वर्ण पदक हैं।

खिताब के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना हैः रजत पाटीदार

बेंगलुरु, एजेंसी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने जीत का चौका लगाते हुए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में शीर्ष स्थान अपने नाम कर लिया है। बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ 5 विकेट से जीत के बाद कप्तान रजत पाटीदार ने माना है कि खिताब के लिए टीम को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है।

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी एलसीजी 146 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में आरसीबी ने 15.1 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। जीत के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा, "हमारी गेंदबाजी शानदार रही। मेरा मानना है कि टॉस जीतना हमारे लिए अहम रहा। तेज गेंदबाजों ने जिस तरह गेंद डाली, वह देखने लायक थी। इस मुकाबले में आरसीबी की टीम से क्रुणाल पंड्या ने 38 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जबकि सुयश शर्मा ने 4 ओवरों में 34 रन दिए। हालांकि, सुयश को विकेट

लियोनेल मेसी कानूनी विवाद में फंसे

दिग्गज फुटबॉलर ने पूरी नहीं की 7 मिलियन डॉलर की शर्त

- **मामला पिछले साल अक्टूबर में मियामी के हॉर्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए अर्जेंटीना बनाम वेनेजुएला फ्रेंडली मैच से जुड़ा है।**

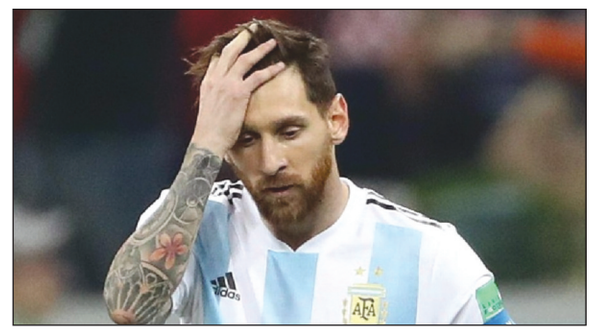

नई दिल्ली, एजेंसी।

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी कानूनी विवाद में फंस गए हैं। मियामी की इवेंट कंपनी वीआईडी म्यूजिक ग्रुप ने मेसी और अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। मामला पिछले साल अक्टूबर में मियामी के हॉर्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए अर्जेंटीना बनाम वेनेजुएला फ्रेंडली मैच से जुड़ा है।

कंपनी का आरोप है कि मेसी ने इस मैच में खेलने के लिए किए गए लगभग 7 मिलियन डॉलर के अनुबंध का उल्लंघन किया। समझौते के तहत उन्हें कम से कम 30 मिनट मैदान पर उतरना था, जब तक कि वे चोटिल न हों। हालांकि, मेसी ने मैच में हिस्सा नहीं लिया और स्टेडियम के एक लग्जरी सुइट से मुकाबला देखा। कंपनी का दावा है कि उनकी अनुपस्थिति से टिकट बिक्री, स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू पर बड़ा असर पड़ा, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ।

वीआईडी म्यूजिक ग्रुप के वकील राल्फ पैटिनो के अनुसार, मेसी की भागीदारी इस डील की एक अहम शर्त थी और यह सीधे तौर पर मैच की व्यावसायिक सफलता से जुड़ी हुई थी। कंपनी ने अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के साथ वेनेजुएला और प्यूर्टो रिको के खिलाफ दो मैत्री मैचों के प्रमोशन का करार किया था।

दिलचस्प यह है कि वेनेजुएला के खिलाफ मैच में नहीं खेलने के बावजूद मेसी अगले ही दिन मेजर लीग सॉकर में अपनी टीम इंटर मियामी सीएफ के लिए उतरे और अटलांटा के खिलाफ 4-0 की जीत में दो गोल दागे, और प्यूर्टो रिको के खिलाफ खेले गए दूसरे फ्रेंडली मैच में हिस्सा लिया।

प्यूर्टो रिको मैच को पहले शिकागो में आयोजित किया जाना था, लेकिन टिकटों की कम बिक्री के चलते इसे मियामी शिफ्ट करना पड़ा। बाद में टिकट की कीमत घटाकर 25 डॉलर तक करनी पड़ी।

मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूंः विराट कोहली

- **सेहत के लिहाज से भी, पिछले चार-पांच दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है।**

बेंगलुरु, एजेंसी।

विराट कोहली ने माना कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 23वें मैच में बुधवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की पांच विकेट की आसान जीत में अहम भूमिका निभाने के बावजूद, वह अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं हैं। 147 रनों का पीछा करते हुए, कोहली ने 49 रनों की शानदार पारी खेली, जिससे आरसीबी ने सिर्फ 15.1 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और पॉइंट्स टेबल में फिर से टॉप पर पहुंच गई।

हालांकि, पूर्व कप्तान ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वह घुटने की समस्या और बीमारी, दोनों से जूझ रहे हैं। मैच के बाद ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए कोहली ने कहा, "पिछले मैच के मुकाबले अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं। पिछले मैच में मेरे घुटने में थोड़ा दर्द था। सेहत के लिहाज से भी, पिछले चार-पांच दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। इसलिए, मैं धीरे-धीरे अपनी पुरानी लय में वापस आ रहा हूं। आज मैंने अच्छी शुरुआत की, इसलिए मैं अपनी एनर्जी लेवल से खुश था। हालांकि, मैं चाहता था कि अपनी पारी को आगे बढ़ाऊं और मैच को फिनिश करूं। कभी-कभी आपको परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। पिच काफी धीमी हो गई थी और मैं बस उसी अंदाज में खेलना जारी रखना चाहता था। लेकिन हां, आखिर में, शायद मुझे ही मैच को फिनिश करना चाहिए था।"

इससे पहले शाम को, आरसीबी के गेंदबाजों ने एलएसजी को 146 रनों पर रोककर जीत की नींव रखी। रासिख सलाम डार ने चार विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने तीन विकेट चटकाए। इस तरह मेजबान टीम ने पूरी पारी के दौरान मेहमान टीम को दबाव में बनाए रखा। टी20 क्रिकेट के बदलते स्वरूप पर बात करते हुए, कोहली ने हालात के हिसाब से ढलने के महत्व पर जोर दिया।

23 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से वापसी कर सकते हैं धोनी

मुंबई, एजेंसी।

चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी अब पिंडली में आये खिंचाव से उबर गये हैं और उनकी शीघ्र टीम में वापसी की संभावनाएं हैं। धोनी की कमी टीम को काफी महसूस हो रही है पर अब क्रिकेट प्रेमियों और प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है। एक रिपोर्ट के अनुसार धोनी 23 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल मैच से वापसी कर सकते हैं। धोनी को इस मैच में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उतारा जा सकता है।

धोनी अभ्यास सत्र दौरान पिंडली में खिंचाव के कारण शुरुआती मैचों से बाहर हो गए थे। हालांकि, अब रिपोर्टों के मुताबिक 44 वर्षीय धोनी अब पूरी तरह से फिट होने के करीब हैं। धोनी के नहीं खेलने पर सीएसके का अब तक का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। टीम ने आईपीएल 2024 में पांच मुकाबले खेले हैं, जिनमें से तीन में उसे हार का सामना करना पड़ा और दो में जीत मिली। शुरुआती तीन हार के बाद, ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली टीम ने पिछले दो घरेलू मैचों में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर अपनी लय हासिल कर ली है। हालांकि, मौजूदा

अगले कुछ महीने में एनडीटीएल की समीक्षा होगी : वाडा अध्यक्ष

नई दिल्ली, एजेंसी। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी (वाडा) के अध्यक्ष विटोल्ड बांका ने बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी (एनडीटीएल) की अगले कुछ महीने में समीक्षा की जायेगी जिसे नाडा ने नियमित प्रक्रिया बताया। वैश्विक डोपिंग रोधी खुफिया और जांच नेटवर्क की आखिरी कांफ्रेंस के बाद यहां प्रेस कांफ्रेंस में उनसे पूछा गया था कि क्या एनडीटीएल के प्रदर्शन की समीक्षा होगी। इस पर उन्होंने कहा, स्थापित नाडा दुनिया भर में वाडा द्वारा मान्यता प्राप्त 29 लेबोरेटरी में से है । एशिया में इसके अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, कतर और थाईलैंड में लैब हैं । भारत में नमूनों की जांच के अलावा एनडीटीएल में श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे दक्षिण एशियाई देशों से आने वाले नमूनों की भी जांच होती है। नाडा के एक सूत्र ने हालांकि पीटीआई से कहा कि वाडा नियमित तौर पर लैब की समीक्षा करता है और इसमें कुछ नया नहीं है। सूत्र ने कहा ,'' एनडीटीएल को वाडा से मान्यता मिली है और लैब के प्रदर्शन की समीक्षा नियमित प्रक्रिया है । वाडा यह करता रहता है। वाडा के अधिकारियों के दौरे के बाद हालांकि एनडीटीएल को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर 2019 से 2021 तक निलंबित कर दिया गया था।

बांका ने हालांकि इस सप्ताह की शुरूआत में लैब का दौरा करके संतोष जताया था। उन्होंने बातचीत में यह भी बताया कि भारत वाडा वैश्विक शिक्षा कांफ्रेंस की मेजबानी का भी इच्छुक है। अब तक चार बार हो चुकी इस कांफ्रेंस का पिछला सत्र 2024 में फ्रांस में हुआ था ।

पीडब्ल्यूएल

एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के 17 में से 11 पदक पीडब्ल्यूएल पहलवानों के नाम

पीडब्ल्यूएल स्टार्स का ग्लोबल स्टेज पर दबदबा जारी

नई दिल्ली, एजेंसी।

इस साल की शुरुआत में प्रोफेशनल रेसलिंग लीग (पीडब्ल्यूएल) की सफल वापसी का असर अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी साफ दिखाई दे रहा है। सीजन 5 में हिस्सा लेने वाले कई भारतीय और विदेशी पहलवानों ने प्रमुख वैश्विक प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है। जनवरी में नोएडा इंडोर स्टेडियम में आयोजित पीडब्ल्यूएल सीजन 5 में विश्वस्तरीय पहलवानों के साथ भारत के स्थापित और उभरते प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिससे यह एक शीर्ष प्रतिस्पर्धी मंच के रूप में और मजबूत हुआ। लीग का प्रभाव अब अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में खिलाड़ियों के प्रदर्शन में नजर आ रहा है, जो एक मजबूत घरेलू प्रतिस्पर्धी ढांचे की अहमियत को दर्शाता है। इस सूची में सबसे आगे सुजीत कलकल रहे हैं, जो पुरुषों के 65 किग्रा वर्ग में दुनिया के शीर्ष पहलवानों में शामिल हो चुके हैं। वर्तमान में ईरान के विश्व चैंपियन और ओलंपिक रजत पदक विजेता रहमान अमौज़ाद के बाद विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज सुजीत ने पीडब्ल्यूएल सीजन 5 में दिल्ली दंगल वॉरियर्स का प्रतिनिधित्व किया था, जहां उन्होंने सात में से छह मुकाबले जीतकर उपविजेता का स्थान हासिल किया। लीग के बाद से सुजीत ने लगातार तीन अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें ज़ाग्रेब और मुहामेत मालो रैंकिंग सीरीज़ के साथ-साथ इस महीने की शुरुआत में किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियन चैंपियनशिप का खिताब शामिल है।

महिला 53 किग्रा वर्ग में मीनाक्षी गोयत भी पीडब्ल्यूएल सीजन 5 की बड़ी सफलता बनकर उभरी हैं। पंजाब रॉयल्स का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने लीग में अपने तीनों मुकाबले जीते और फिर नेशनल ट्रायल्स में अंतिम पंघल को हराकर भारतीय टीम में जगह बनाई। इसके बाद उन्होंने मुहामेत मालो टूर्नामेंट और बिश्केक में एशियन चैंपियनशिप दोनों में रजत पदक जीतकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी दावेदारी मजबूत की है। अन्य प्रमुख प्रदर्शनकर्ताओं में ओलंपिक रजत पदक विजेता अमन सहरावत (पुरुष 61 किग्रा), जिन्होंने टाइगर्स ऑफ मुंबई डैंगल्स के लिए खेलते हुए ज़ाग्रेब और बिश्केक में रजत पदक जीते, जबकि दिनेश धनखड़ (पुरुष 125 किग्रा) ने पंजाब रॉयल्स के लिए दोनों प्रतियोगिताओं में कांस्य पदक हासिल किए। हरियाणा थंडर्स की नेहा सांगवान ने भी मुहामेत मालो में रजत और बिश्केक में कांस्य पदक जीतकर प्रभावित किया।सबसे उत्साहजनक प्रदर्शन उभरते हुए भारतीय पहलवान अभिमन्यु (पुरुष 70 किग्रा) का रहा। 24 वर्षीय सीआईएसएफ कांस्टेबल, जिन्होंने लीग में यूपी डॉमिनेटर्स का प्रतिनिधित्व किया, ने बिश्केक में फाइनल में मंगोलिया के दिग्गज और पूर्व एशियन गेम्स चैंपियन टॉमोर-ओचिरिन तुलगा को हराकर स्वर्ण पदक जीता।

लीग का प्रभाव अंतरराष्ट्रीय सितारों पर भी देखने को मिला। कनाडा की विश्व पदक विजेता कार्ला गोडिनेज गोंजालेज, जिन्होंने दिल्ली दंगल वॉरियर्स का प्रतिनिधित्व किया, ने ज़ाग्रेब में रजत पदक जीता, जबकि जापान की दिग्गज पहलवान यूई सुसाकी, जो खिताब जीतने वाली हरियाणा थंडर्स टीम का हिस्सा थीं, ने बिश्केक में एक और एशियाई खिताब अपने नाम किया।

'सैयारा' के बाद इस फिल्म में नजर आएंगे अहान पांडे, अली अब्बास जफर करेंगे निर्देशन

'सैयारा' फेम एक्टर अहान पांडे एक एक्शन-रोमांटिक फिल्म में नजर आएंगे। आज अली अब्बास जफर ने इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए फिल्म से अहान पांडे का पहला लुक शेयर किया है, जिस पर फैंस दिल हार बैठे हैं।

शूटिंग हुई शुरू

अहान पांडे की इस फिल्म की शूटिंग आज से आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। जल्द ही मुख्य अभिनेत्री और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की जाएगी। फिल्म का निर्माण वाईआरएफ कर रहा है। इसकी शूटिंग मुंबई और विदेशों में होगी। इस फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर ने इंस्टाग्राम पर अहान की एक खास तस्वीर शेयर की और लिखा, 'और शुरू हो गई...' अहान पांडे की इस फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर ने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें शेयर की हैं। पहली तस्वीर अहान पांडे की है। इस तस्वीर में अहान के चेहरे का कुछ हिस्सा साफ नजर आ रहा है, क्योंकि बाकी की तस्वीर धुंधली है। छोटे बाल में अहान का यह लुक कमाल का लग रहा है।

सेलेब्स और फैंस के कमेंट्स

अहान की इस दूसरी फिल्म के पहले लुक ने सेलेब्स और फैंस का दिल जीत लिया है। अभिनेता अर्जुन कपूर ने लिखा, 'मास' और साथ ही फायर इमोजी बनाया है। टीवी अभिनेता हितेन तेजवानी ने लिखा, 'बधाई हो अली सर', अहान की मां डीन ने लिखा, 'पूरी टीम को शुभकामनाएं', रजत बेदी ने लिखा, 'बधाई हो अली भाई', एक फैन ने लिखा, 'बहुत ज्यादा उत्साहित हूं', दूसरे फैन ने लिखा, 'अहान तुम कमाल कर दोगे', वहीं कई फैंस अहान के इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

अली और आदित्य की जोड़ी

'सैयारा' जैसी लव स्टोरी करने के बाद अब एक्शन-रोमांस फिल्म में आहान को एक बिल्कुल नए अंदाज में नजर आएंगे। यह फिल्म आदित्य चोपड़ा और अली अब्बास जफर की पांचवीं फिल्म है, जिनकी जोड़ी ने 'मेरे ब्रदर की दुल्हन', 'गुंडे', 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' जैसी हिट फिल्में दी हैं।

जान्हवी कपूर ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में की खुलकर बातचीत

जान्हवी कपूर हाल ही में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' फिल्म में नजर आई थी। इनमें उनके साथ वरुण धवन, रोहित शरफ और सान्या मल्होत्रा भी अहम किरदार में नजर आए थे। राज शमानी को दिए इंटर्व्यू में जान्हवी कपूर ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में खुलकर बातचीत की, और बताया कि उन्हें बॉयफ्रेंड के साथ कितना सुरक्षित और अपनापन महसूस होता है।

कौन हैं जान्हवी कपूर के बॉयफ्रेंड?

जान्हवी कपूर और शिखर पहाड़िया एक दूसरे को काफी वक्त से डेट कर रहे हैं। वे अक्सर पार्टी, फैमिली फंक्शन और इवेंट्स में साथ नजर आते हैं। हाल ही में राज शमानी के साथ पॉडकास्ट में उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलकर चर्चा की। उनके साथ मैं बिल्कुल बच्चे जैसी बन जाती हूं जान्हवी ने शिखर के बारे में बात करते हुए कहा, 'प्यार की वजह से मैं उनके साथ खुद का सबसे सच्चा वर्जन बन पाती हूं। मुझे एक ऐसा सुरक्षित एहसास मिला है, जहां मैं अपने दिल की बात सुन सकती हूं और उस पर भरोसा कर सकती हूं। उनकी मौजूदगी हमेशा मुझे यही एहसास देती है।' उन्होंने आगे कहा, 'उनके साथ मैं बिल्कुल बच्चे जैसी बन जाती हूं। यह एक ऐसी जगह है जहां मैं बिना किसी झिझक के खुद रह सकती हूं। उनके साथ मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है।'

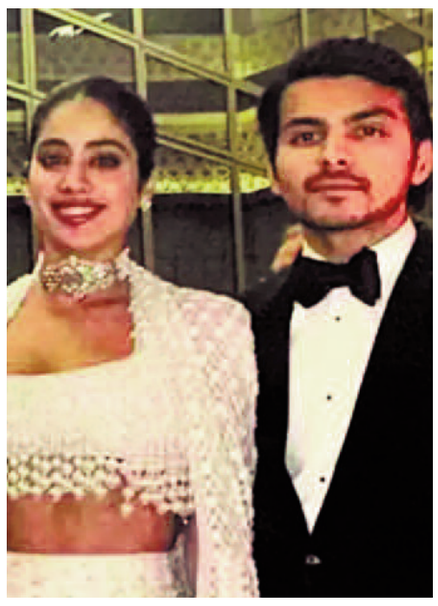

शिखर पहाड़िया के बारे में

शिखर पहाड़िया, पूर्व गृह मंत्री सुशीलकुमार शिंदे के नाती हैं। उनकी मां स्मृति शिंदे एक एक्ट्रेस हैं। उनके बड़े भाई वीर पहाड़िया ने हाल ही में फिल्म स्काई फोर्स से बॉलीवुड डेब्यू किया, जिसमें अक्षय कुमार, निम्रत कौर और सारा अली खान भी नजर आए।

जान्हवी कपूर का अगला प्रोजेक्ट

वर्क फ्रंट की बात करें तो जान्हवी कपूर जल्द ही लक्ष्य और टाइगर श्रोफ के साथ धर्मा प्रोडक्शंस की अगली एक्शन फिल्म 'लग जा गले' में नजर आ सकती हैं। खबरों के मुताबिक, इस फिल्म की शूटिंग पिछले महीने मुंबई में शुरू हो चुकी है, जिसे राज मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं।

पृथ्वीराज ने पूरी की 'वाराणसी' की शूटिंग

अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन ने एसएस राजामौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग का एक अहम शेड्यूल पूरा कर लिया है। अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन ने एसएस राजामौली की आगामी फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग पूरी होने की खुशखबरी दी है। शूटिंग खत्म होने के साथ उन्होंने फिल्म की रिलीज के लिए एक साल की उलटी गिनती भी शुरू कर दी है। पृथ्वीराज ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सेट से एक चीट मील की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर के साथ अभिनेता ने लिखा, 'बहुत मेहनत वाले शेड्यूल का आखिरकार अंत हो गया। चीट मील का पूरा मजा लिया।' इसके साथ ही पृथ्वीराज सुकुमारन ने फिल्म के निर्माता केएल नारायण को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट भी बताई। पृथ्वीराज ने लिखा, '7 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में मिलते हैं।' फिल्म 'वाराणसी' में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह एक तेलुगु एडवेंचर ड्रामा फिल्म है। इसका निर्देशन एसएस राजामौली ने किया है। फिल्म का बजट 1300 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। फिल्म में महेश बाबू रुद्र और भगवान राम के दोहरे रोल में दिखेंगे। प्रियंका चोपड़ा मंदाकिनी और पृथ्वीराज सुकुमारन कुंभ के रोल में नजर आएंगे।

साउथ एक्टर विष्णु विशाल ने सोशल मीडिया से लिया ब्रेक

एक्टर-प्रोड्यूसर विष्णु विशाल ने कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। इनमें से कई फिल्में सुपरहिट रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए ब्रेक लेने का फैसला किया है। उन्होंने अपने फैंस को भरोसा दिलाया है कि वे जल्द ही अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स से जुड़ी नई जानकारियों के साथ वापस लौटेंगे।

विष्णु विशाल ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक

एक्टर ने सोशल मीडिया से ब्रेक लेने वाली जानकारी देते हुए लिखा 'सोशल मीडिया से एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। जल्द ही फिल्मों से जुड़ी नई जानकारियों के साथ वापस आऊंगा। एक्टर 'वेनिला कबाड़ी कुझु', 'कुल्नारी कूट्टम', और 'रतसासन' के लिए जाने जाते हैं।

तीसरी बार इस निर्देशक के साथ कर रहे काम

यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब रामकुमार के निर्देशन में बन रही उनकी अगली फिल्म 'इरंडु वानम' को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता बढ़ रही है। 'मुंडासुपत्ती' और 'रतसासन' की सफलता के बाद, यह जोड़ी तीसरी बार एक-साथ काम कर रही है।

पूरी हुई अपकमिंग फिल्म की शूटिंग

पिछले साल जून में, विष्णु विशाल ने इस बात की पुष्टि की थी कि फिल्म 'इरंडु वानम' की शूटिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया था कि शूटिंग 150 दिनों में पूरी हुई थी। सत्य ज्योति फिल्म्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म में मामिता बैजू मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आएंगी। फिल्म का पहला लुक पोस्टर, जो पहले ही जारी किया जा चुका है, काफी दिलचस्प है। इसमें दोनों मुख्य कलाकार बादलों पर एक-दूसरे की विपरीत दिशा में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

विष्णु का वर्कफ्रंट

पिछली बार फिल्म 'आर्यन' में नजर आए विष्णु विशाल के पास अभी 'गट्टा कुश्ती' का सीक्वल भी पाइपलाइन में है, जिसका निर्देशन चेल्ला अय्यावु कर रहे हैं। वहीं, उनकी लंबे समय से अटकी हुई फिल्म 'मोहनदास' अभी तक रिलीज नहीं हो पाई है।

परिणीति चोपड़ा की नई पारी शुरू, 'मॉम टॉक्स' शो की होस्ट बनीं

परिणीति चोपड़ा ने अपने करियर में एक नया और खास चैप्टर जोड़ते हुए टॉक शो होस्ट के रूप में शुरुआत कर दी है। उनके इस नए सफर पर पति और सांसद राघव चड्ढा ने भी सोशल मीडिया पर इमोशनल नोट शेयर कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। परिणीति ने हाल ही में अपने टॉक शो 'मॉम टॉक्स' का टीजर जारी किया है। यह शो मातृत्व, प्रेग्नेंसी और बच्चों की परवरिश से जुड़े उन पहलुओं पर आधारित है, जिन पर अक्सर खुलकर बात नहीं की जाती। खास बात यह है कि यह परिणीति का पहला टॉक शो है, जिसमें वह होस्ट की भूमिका में नजर आएंगी। पिछले साल मां बनीं परिणीति इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने अनुभवों के साथ-साथ अन्य लोगों की कहानियां भी सामने लाना चाहती हैं। उनका मानना है कि मातृत्व से जुड़े कई पहलू आज भी समाज में झिझक के साथ देखे जाते हैं। राघव चड्ढा ने उनका हौसला बढ़ाते हुए लिखा, 'बहुत गर्व है। बधाई हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह शो मातृत्व, प्रेग्नेंसी और बच्चों की परवरिश से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित होगा

रणवीर सिंह कर सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पर फिल्म: आदित्य धर के साथ फिर बन सकती है जोड़ी

धुरंधर फ्रैंचाइजी की सफलता के बाद अब सभी की नजर इस बात पर है कि डायरेक्टर आदित्य धर का अगला प्रोजेक्ट कौन सा होगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि आदित्य धर रणवीर सिंह के साथ भी एक प्रोजेक्ट पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया, आदित्य धर इस समय तीन स्क्रिप्ट पर विचार कर रहे हैं। इनमें द इम्मॉर्टल अश्वत्थामा, एक ऐतिहासिक फिल्म और एक बड़े लेवल की स्पोर्ट्स फिल्म शामिल है। उनकी अगली फिल्म इनमें से कोई एक हो सकती है, जब तक कि कोई नया प्रोजेक्ट प्राथमिकता में न आ जाए। एक सूत्र का कहना है कि द इम्मॉर्टल अश्वत्थामा आदित्य का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इस फिल्म पर उन्होंने पहले काफी काम किया था, लेकिन ज्यादा बजट के कारण इसे रोक दिया गया था। अब उनकी सक्सेस और इंडस्ट्री में बढ़ते भरोसे के चलते इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की संभावना बनी हुई है।

चंद्रगुप्त मौर्य पर आधारित फिल्म पर चर्चा

एक अन्य सूत्र के मुताबिक, आदित्य धर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल पर आधारित ऐतिहासिक फिल्म बनाने में भी दिलचस्पी रखते हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर उनकी रणवीर सिंह के साथ पिछले साल से बातचीत चल रही है। धुरंधर की सफलता के बाद दोनों फिर से इस पर चर्चा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, यह विषय अभी तक ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है और इसमें ड्रामा, एक्शन और पॉलिटिक्स जैसे कई मजबूत एलिमेंट हैं। अगर फिल्म अश्वत्थामा नहीं बनती, तो यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा, एक स्पोर्ट्स ड्रामा भी शुरुआती स्टेज में है, जो बड़े लेवल पर बनाया जा सकता है। हालांकि इसकी जानकारी अभी साफ नहीं है।

कहा जा रहा है कि डायरेक्टर के पास कई प्रोजेक्ट्स के विकल्प मौजूद हैं, लेकिन वे एक ब्रेक के बाद ही अगले प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ेंगे। डायरेक्टर ने पिछले तीन साल रणवीर सिंह के साथ 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी पर काम करते हुए बिताए हैं। इसलिए, अब वे कुछ समय का ब्रेक लेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक बात पक्की है कि आदित्य धर की अगली फिल्म और बड़े कैनवास पर बनने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार, आदित्य धर एक बार फिर रणवीर के साथ काम करने के इच्छुक हैं। इस बार वे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक पर आधारित एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म पर काम करेंगे। आदित्य धर पिछले साल से ही रणवीर के साथ बातचीत कर रहे हैं।

क्यों रुका 'द इमॉर्टल अश्वत्थामा' पर काम

बात करें 'द इमॉर्टल अश्वत्थामा' की तो यह आधित्य धर के उन पैशन प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसे कथित तौर पर बजट संबंधी दिक्कतों के चलते कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। हालांकि, 'धुरंधर' से अच्छी-खासी कमाई के बाद इस फिल्म पर फिर से काम शुरू होने की संभावना बन गई है। लेकिन, अगर इसे हरी झंडी नहीं मिलती है, तो कहा जा रहा है कि यह ऐतिहासिक ड्रामा ही आदित्य धर का अगला प्रोजेक्ट है। इसके अलावा, ऐसी भी चर्चा है कि आदित्य धर एक स्पोर्ट्स ड्रामा पर भी काम कर रहे हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, **सुनील कुमार** द्वारा वी-22 खजूर वाली गली नम्बर-2 अरविंद नगर, घोंडा दिल्ली-110053 से प्रकाशित एवं कारे प्रिंटिंग प्रेस 574ए विजय पार्क गली नम्बर-2 मौजपुर दिल्ली-110053 से मुद्रित। किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली न्यायालय में ही होगा। **सम्पादक : सुनील कुमार** RNI NO.- DELHIN/2007/22401